

Discover your divinity with us
A/C Showroom
ज्ञान गंगा ॐ मूर्ति माला केन्द्र
उजाला भवन स्टेशन रोड, दुर्गा
0788-4030383, 3293199
भगतान के वस्त्र, श्रृंगार
मूर्तियां एवं सज्ज
पूजन सामग्री
संगमरमर व पीतल की
मूर्तियां राशि रत्न
एवं उपरतन उपलब्ध

राष्ट्र एवं राज्य के प्रगति पथ पर...

समय दर्शन



रायपुर, दुर्ग एवं जगदलपुर से प्रकाशित

संस्थापक : स्व. श्रीमती निलिमा खड़तकर

निष्पक्ष निर्भीक खबरों के साथ

दुर्गा राहर में
सुप्रसिद्ध
ज्योतिषाचार्य
पं. एम.पी. शर्मा/
मो. 8109922001
फीस 251/- मात्र
पता:- श्री दुर्गा ज्योतिष कार्यालय
सिकोला भाटा, सब्जी मार्केट के
सामने, धमधा नाका, दुर्गा

वर्ष 15, अंक 118

पृष्ठ 8, मूल्य 3.00 रुपये

दुर्गा, मंगलवार 17 मार्च 2026

www.samaydarshan.in

सांक्षिप्त समाचार

यमुना अथॉरिटी के इंडस्ट्रियल पार्कों में आणगी रफतार

ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में बन रहे विभिन्न इंडस्ट्रियल पार्कों के निर्माण और वहां इकाइयों की स्थापना में अब और तेजी आणगी। शनिवार को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (औद्योगिक विकास) एवं यमुना अथॉरिटी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने मेडिकल डिवाइस पार्क स्थित एडमिनिसट्रेशन बिल्डिंग में समीक्षा बैठक की और चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। बैठक के दौरान अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शैलेंद्र कुमार भाटिया ने एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन) के माध्यम से क्षेत्र में विकसित हो रहे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी। उन्होंने मेडिकल डिवाइस पार्क, अपरल पार्क, एमएसएमई पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, टॉय पार्क, सेमीकंडक्टर पार्क, डेटा सेंटर पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर और जनरल इंडस्ट्री सेक्टरों की वर्तमान स्थिति और अब तक हुई प्रगति के बारे में विस्तार से बताया।

बहुजन समाज के सम्मान और संविधान की रक्षा के लिए खड़ी रहेगी कांग्रेस

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और समाज सुधारक कांशीराम की जयंती के मौके पर उन्हें नमन किया है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज की भागीदारी, सम्मान और संविधान की रक्षा के लिए पहले भी खड़ी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, बहुजन नायक कांशीराम की जयंती पर उन्हें सादर नमन। गरीबों, दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए उनका अथक संघर्ष और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है। उनका मानना था संविधान ही दलितों, पिछड़ों और वंचितों की असली ताकत है। राहुल गांधी ने लिखा, संविधान आज खतरे में है। बाबा साहेब के संविधान की शपथ ले कर सत्ता में बैठने वाले ही उसको कमजोर करने पर तुले हैं।

मिडिल ईस्ट में हालात की समीक्षा के बाद भारतीय दूतावास ने जारी किया नया अपडेट

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में ईरान और इजरायल-अमेरिका हमलों की वजह से भारी तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। इसका असर इन देशों में रहने वाले छात्रों की पढ़ाई पर भी देखने को मिल रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने जीसीसी में 12वीं कक्षा के बोर्ड एजाज के बारे में 15 मार्च 2026 का एक सर्कुलर जारी किया है। यह एडवाइजरी बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के लिए जारी की गई है। ओमान में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी में लिखा, यह 01.03. 2026, 03.03. 2026, 05.03. 2026, 07.03. 2026 और 09.03. 2026 के सर्कुलर के बाद आया है।

कैसे लगी कटक के मेडिकल कॉलेज में आग

सात लोग जिंदा जले तो तीन ने इलाज के दौरान तोड़ा दम

नई दिल्ली/ एजेंसी

ओडिशा के कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सोमवार सुबह एक भयंकर अग्निकांड हुआ, जिसमें 10 मरीजों की मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। आग लगने के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशकत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत और बचाव कार्य भी चलाया गया, जिसके तहत आईसीयू में भर्ती मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। आग की वजह से आईसीयू में धुआं फैल गया, जिससे

वहां भर्ती गंभीर मरीजों की हालत और बिगड़ गई। आग के कारण 23 मरीजों में से सात की मौत हो गई। बाद में इलाज के दौरान तीन और मरीजों ने दम तोड़ दिया, जिससे कुल मृतकों की संख्या 10 हो गई। उन्होंने यह भी बताया कि मरीजों को बचाने के दौरान अस्पताल के कई कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने के साथ-साथ राहत कार्य भी किया। अस्पताल परिसर में पुलिस और प्रशासन की टीमों तैनात हैं और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं और कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार



व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता नवीन पटनायक ने भी इस घटना पर गहरा

दुख व्यक्त किया है। उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने राज्य सरकार से घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की अपील भी की। वहीं, राज्यपाल हरि बाबू कम्भमपति ने भी इस दर्दनाक घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि ट्रीमा केयर आईसीयू में लगी आग की घटना बेहद दुखदा है। उन्होंने प्रभावित मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और इलाज जारी रखने के प्रयासों की सराहना की। राज्यपाल ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की और प्रशासन को पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने का निर्देश दिया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। यह हादसा ओडिशा के स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है और राज्य सरकार को भविष्य में अस्पतालों की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की खामियों को सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

सीएम ने किया अस्पताल का दौरा-जाना हालचाल

मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सोमवार सुबह कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का दौरा किया। सीएम हॉस्पिटल के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि यहां ट्रीमा केयर आईसीयू में आग लग गई। पांच घायल व्यक्तियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिन 10 लोगों की मौत हुई है, वे ट्रीमा केयर के आईसीयू में भर्ती मरीज थे। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के तुरंत बाद अस्पताल में इलाज करा रहे 23 मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया। उन्होंने बताया कि दुर्भाग्य से आईसीयू में 10 मरीजों की मौत हो गई।

असम विधानसभा चुनाव 2026: 126 सीटें

हिमंता बनाम गौरव....की जंग में कौन मारेगा बाजी

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य में आगामी 9 अप्रैल को महज एक चरण में मतदान होना तय किया गया है, जबकि 4 मई को नतीजे आएंगे। मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच है। असम की सियासी बिसात बिछ चुकी है। रविचार को चुनाव आयोग द्वारा तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में चुनावी सरगमियां तेज हो गई हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली 'डबल इंजन' सरकार



अपनी उपलब्धियों के दम पर सत्ता बचाने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ गौरव गोरोई के चेहरे के साथ कांग्रेस दलबदल के झटकों से उबरकर वापसी की राह देख रही है। आइए, राज्य के इस महासंग्राम को बारीकी से समझते हैं। बीजेपी की रणनीति ताकत और चुनौतियां/ताकत भाजपा इस बार अपने मजबूत संगठनात्मक आधार और विभाजित विपक्ष के भरोसे मैदान में है।



क्षेत्रीय तनाव के बीच ईरान से निकाले जाने के बाद, वहां से लौटे छात्र नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर पहुंचे।

सुप्रीम कोर्ट ने टाली सुनवाई

संभल मस्जिद सर्वे पर सस्पेंस बरकरार

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर चल रहे विवाद में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी थी, जो टल गई है। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद करने का निर्देश दिया है। यह मामला उस याचिका से जुड़ा है, जिसे मुस्लिम पक्ष ने दायर कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में निचली अदालत द्वारा संभल की शाही जामा मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से सर्वे कराए जाने के निर्देश को बरकरार



रखा था। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि निचली अदालत का इस तरह से सर्वे कराने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, मस्जिद से जुड़े विवाद में कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराने का आदेश देना न्यायिक प्रक्रिया और अधिकार क्षेत्र से परे है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की अधिसूचना जारी

सीएम के बाद जदयू प्रमुख का पद भी छोड़ेंगे नीतीश कुमार...

नई दिल्ली/ एजेंसी

राज्यसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। फिलहाल नीतीश कुमार ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जदयू की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक 22 मार्च को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद 24 मार्च तक नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख तय की गई है। अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में आते हैं, तो 27 मार्च को चुनाव कराया



जाएगा। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार के ही दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावना है। राज्यसभा सदस्य रहते हुए वे पार्टी की कमान अपने ही हाथों में बनाए रखेंगे। वहीं, वेगुसराय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री

नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर राजनीतिक कयास तेज हो गए। कार्यक्रम में सम्राट चौधरी के प्रति दिखे समर्थन को देखते हुए कई लोग उन्हें भविष्य का मुख्यमंत्री बताने लगे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत वेगुसराय पहुंचे नीतीश कुमार के मंच पर पहुंचते ही संचालक ने यहां तक कह दिया कि यह मुख्यमंत्री के रूप में उनकी अंतिम यात्रा हो सकती है। इस घोषणा के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। इसी दौरान नीतीश कुमार अपने भाषण के दौरान उस समय चर्चा में आ गए, जब कुछ महिलाएं बीच कार्यक्रम से ही जाने लगीं।

अगली बार गोली

माथे में मारेंगे, सिंगर बादशाह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी

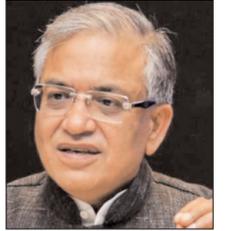
चंडीगढ़। मशहूर बॉलीवुड सिंगर और रैपर बादशाह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एक तरफ हरियाणा पुलिस की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई की तलवार लटकती हुई है, वहीं अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से उन्हें जान से मारने की धमकी दिए जाने का दावा सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पानीपत में हाल ही में हुई फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी लेते हुए बिश्नोई गैंग ने एक नोट जारी किया है, जिसमें कथित तौर पर बादशाह को धमकी दी गई है। इस नोट के सामने आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है और सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं।

बंगाल में चुनाव आयोग का एक्शन

डीजीपी से लेकर मुख्य सचिव तक बदले -ज्ञानेश कुमार

नई दिल्ली/ एजेंसी

पश्चिम बंगाल को चुनावी जंग शुरू होने से पहले ही दिल्ली से एक ऐसा आदेश आया है जिसने राज्य सचिवालय 'नबना' में हड़कंप मचा दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ओर से रविवार को चुनाव शांतिपूर्ण कराने के आश्वासन के बाद वे कार्रवाई की गईं। आयोग ने सोमवार को राज्य के पुलिस और प्रशासनिक अमले की पूरी तस्वीर बदल दी है। यह कार्रवाई न केवल निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए है, बल्कि उन अधिकारियों को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखने के लिए भी है



जिन पर पक्षपात के आरोप लगाए जा सकते थे। चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग के शीर्ष स्तर पर तत्काल प्रभाव से बदलाव किए हैं। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी सिद्ध नाथ गुप्ता को

पश्चिम बंगाल का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है, उन्होंने पीयूष पांडे की जगह ली है। इसके अलावा, कोलकाता पुलिस की कमान अब अजय कुमार नंद के हाथों में होगी, जिन्हें सुप्रतिम सरकार की जगह नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। आयोग ने कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए नटराजन रमेश बाबू को डीजी और अजय मुकुंद रानाडे को एडिशनल डीजी (ऑन एंड आर्डर) के पद पर तैनात किया है। पुलिस के साथ-साथ राज्य की नौकरशाही में भी एक अभूतपूर्व घटनाक्रम देखने को मिला है।

विधानसभा में जमकर गुंजा मामला....

अमानक चावल की खरीदी पर विपक्ष का बहिर्गमन

रायपुर। समय दर्शन

विधानसभा में आज अमानक चावल की खरीदी का मामला जमकर गुंजा। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल पर दोषी लोगों को बचाने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। प्रश्नकाल में व्यास कश्यप के सवालों की झड़ी थी। कश्यप के सवाल को खड़ा कर दिया कि क्या कोरवा जिले में नागरिक आपूर्ति निगम अंतर्गत संचालित संग्रहण केन्द्रों/गोदामों में दूसरे जिले की आईडी एवं ओटीपी का उपयोग कर अमानक (सब स्टैंडर्ड) चावल की खरीदी की गई? कुल कितनी मात्रा में अमानक/घटिया चावल की खरीदी की गई? उसकी अनुमानित वित्तीय राशि कितनी है? क्या गुणवत्ता परीक्षण

(कालिटी इंस्पेक्शन) नियमानुसार किया गया था? यदि किया गया तो अमानक चावल कैसे स्वीकार हुआ? प्रकरण में अब तक किन अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई? क्या किसी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई? खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की ओर से जवाब आया कि इस प्रकरण में जिला बालोद, बेमेतरा एवं जशपुर के कर्मचारियों की आईडी का उपयोग किया गया। खरीदे गये चावल में से 8153.48 क्विंटल चावल वितरण योग्य मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया, जिसकी अनुमानित वित्तीय राशि लगभग 3 करोड़ 34 लाख रुपये है। वितरण के योग्य नहीं पाए गए चावल का गुणवत्ता परीक्षण तत्समय नियमानुसार नहीं किए जाने के कारण अमानक चावल जमा हुए। प्रकरण



में एक कनिष्ठ सहायक एवं एक कनिष्ठ तकनीकी सहायक को निलंबित किया गया है। किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। व्यास कश्यप ने कहा कि अमानक चावल के पीछे बाहरी व्यक्तियों से खरीदी का मामला है। 17 करोड़ के चावल का मामला है। जो अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं, वो खुद जांच के दायरे में हैं। उन्हें लकजरी होटल में ठहराया गया। उनके लिए कपड़े खरीदे गए। क्या उन जांच अधिकारियों के खिलाफ भी जांच की जांच के लिए दल का गठन किया गया है। गुणवत्ता की जांच की गई। कनकी की मात्रा का परीक्षण किया गया। चावल अमानक पाए जाने पर दो कर्मचारी निलंबित किए गए। 10

कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। व्यास कश्यप ने कहा कि आपने जो कार्यवाही की उससे इंकार नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि पूरे मामले में लीपापोती की गई है। जिसके खिलाफ कार्यवाही हुई उसके नाम का यहां उल्लेख तक नहीं किया गया। इस मामले में राईस मिलरों की संलिप्तता रही मामला है। चार महीने हो गए। आखिर दोषी लोगों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही कब करेंगे?

मंत्री ने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा कार्यवाही करेंगे। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि मंत्री दोषी लोगों को बचा रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस विधायकगण सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन से वाक आउट कर गए।

संक्षिप्त समाचार

मनरेगा पर विधानसभा घेराव में राजनांदगांव से सैकड़ों कार्यकर्ता जाएंगे : विपिन यादव



राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 17 मार्च 2026 को रायपुर में आयोजित मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत प्रस्तावित विधानसभा घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा जिले के समस्त ब्लॉकों में बैठकें लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। इस संबंध में जिलेभर में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच व्यापक जनसंपर्क कर आंदोलन को मजबूत बनाने की रणनीति भी तय की गई है। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी अनीस खान द्वारा जारी बयान में जिलाध्यक्ष विपिन यादव ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देशानुसार तथा प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और राज्य के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में मनरेगा में किए गए श्रमिक विरोधी और जनविरोधी परिवर्तनों के खिलाफ प्रदेशभर के कांग्रेसजन रायपुर में विधानसभा का घेराव करेंगे। विपिन यादव ने बताया कि राजनांदगांव जिले के सभी ब्लॉकों में बैठकें लेकर कार्यकर्ताओं को आंदोलन की रूपरेखा से अवगत कराया गया है और रायपुर जाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के विभिन्न ब्लॉकों से सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रायपुर पहुंचकर विधानसभा घेराव में शामिल होंगे और श्रमिकों व ग्रामीणों के अधिकारों की आवाज बुलंद करेंगे। जिलाध्यक्ष विपिन यादव ने जिले के सभी वरिष्ठ कांग्रेसजनों, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में रायपुर पहुंचकर इस महत्वपूर्ण आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मनरेगा गरीबों, मजदूरों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है, लेकिन वर्तमान सरकार इसके स्वरूप को कमजोर करने का काम कर रही है। विपिन यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी श्रमिकों, किसानों और ग्रामीणों के अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी और मनरेगा में किए गए श्रमिक विरोधी निर्णयों के खिलाफ सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष जारी रखेगी।

प्रधान जिला न्यायाधीश, कलेक्टर ने किया जिला जेल का निरीक्षण



जांजगीर-चांपा // समय दर्शन //माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये निर्देशानुसार बोर्ड आफ विजिटर्स के द्वारा जिला जेल जांजगीर का निरीक्षण प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर चांपा श्री शक्ति सिंह राजपूत, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर श्री मनोज कुमार कुशवाहा, कलेक्टर श्री जमनेजय महोबा, नगर पुलिस अधीक्षक जांजगीर सुश्री योगिता खापेडे की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक श्री डी.डी. टोडर, अधिवक्ता लीगल एट डिफेंस कार्टिसल श्री सत्यनारायण सिंह ठाकुर, श्री विनोद कुमार कश्यप, श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल, श्री अशोक यादव, पैरालीगल वॉलेंटियर श्री लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल, श्री जयराम गढ़वाल सहित संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान बंदियों को दी जाने वाली विधिक सहायता के संबंध में जिला जेल लीगल एट क्लिनिक की व्यवस्थाओं, जेल में स्थापित व्हीसी कक्ष, जेल बिल्डिंग की व्यवस्था, बैरकों के निर्माण, मुलाकात कक्ष, बंदियों को प्रदत्त सुविधा, भोजन की गुणवत्ता, शिकायत पेटी, पेयजल की व्यवस्था, बंदियों की कपड़ा की दशा, शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था के साथ-साथ बंदियों के प्रकरण में आने वाली समस्याओं के संबंध में जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

पय्यूर-रेडी फैसिलिटेशन स्किल्स कार्यशाला सम्पन्न

धमतरी। जिला प्रशासन धमतरी द्वारा प्रथम एजुकेशन फंडेशन तथा आईसीआईसीआई फंडेशन के सहयोग से दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पय्यूर-रेडी फैसिलिटेशन स्किल्स का सफल आयोजन कुरुद स्थित पीएसईई सेंटर में किया गया। इस कार्यशाला में जिले के सभी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के प्रशिक्षण अधिकारियों एवं प्राचार्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य बदलती औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षकों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना तथा प्रशिक्षण पद्धतियों को अधिक प्रभावी, नवाचारपूर्ण और परिणाममुखी बनाना था।

जनपद सीईओ को अधिकार नहीं, फिर भी पंचायत सचिव के रोके गए वेतन

जनपद सीईओ को पंचायत सचिव के शिकायत पर जिला कार्यालय से नोटिस जारी

छुईखदान (समय दर्शन)। ग्राम पंचायत दुनिया के सचिव के वेतन भुगतान को लेकर जनपद पंचायत छुईखदान में विवाद गहराता नजर आ रहा है। अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले सचिव बुधार राम धुर्वे का वेतन कई महीनों से नहीं मिलने पर ग्राम पंचायत दुनिया के सरपंच और ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंडई-छुईखदान को ज्ञापन सौंपकर 18 मार्च को जनपद पंचायत कार्यालय का घेराव और धरना-प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। ज्ञापन में कहा गया है कि सचिव का कई माह का वेतन रोके दिया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सरपंच का आरोप : बिना कारण रोका गया वेतन- ग्राम पंचायत दुनिया के सरपंच मंगलू साहू ने कहा कि पंचायत सचिव

नियमित रूप से पंचायत के कार्यों में उपस्थित रहते हैं और शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। इसके बावजूद उनका वेतन रोके दिया गया है। सरपंच का कहना है कि इस संबंध में एक माह पहले भी जनपद पंचायत कार्यालय में आवेदन देकर सचिव का वेतन जारी करने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

तीन दिन में भुगतान नहीं तो आंदोलन- सरपंच और ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि सचिव का रूका हुआ वेतन तीन दिन के भीतर जारी नहीं किया गया तो 18 मार्च को सुबह 11 बजे जनपद पंचायत छुईखदान कार्यालय का घेराव कर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इस आंदोलन में सरपंच पंचद ग्रामीण और पंचायत प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल होंगे।

जनपद सभापति सुधीर गोलछ ने उठया मुद्दा- जनपद सभापति सुधीर गोलछ ने भी इस मामले में नाराजगी जताते हुए कहा कि संबंधित सचिव नियमित रूप से



पंचायत में उपस्थित होकर कार्य कर रहे हैं और सरपंच द्वारा उनकी उपस्थिति की लिखित जानकारी भी दी जा चुकी है। इसके बावजूद उनका वेतन लंबित रखा गया है, जो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सचिव के खिलाफ न तो सरपंच, न पंचों और न ही ग्रामवासियों द्वारा कोई शिकायत की गई है।

आज-कल भुगतान होगा कहरक टालने का आरोप- गोलछ ने आरोप लगाया कि वेतन भुगतान के मामले में जनपद पंचायत कार्यालय की ओर से लगातार आज-कल भुगतान कर

देंगे कहरक टालमटोल की जा रही है। उन्होंने बताया कि जब सरपंच, पंच और ग्रामीण आंदोलन के लिए समर्थन लेने उनके पास पहुंचे तब पूरे मामले की जानकारी सामने आई। उन्होंने कहा कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

सचिव ने भी लिखा पत्र, बताया आर्थिक संकट- इधर पंचायत सचिव बुधार राम धुर्वे ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र लिखकर रुका हुआ वेतन दिला

की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा कि कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है

और परिवार के भरण-पोषण व इलाज में भी परेशानी हो रही है। सचिव ने प्रशासन से जल्द भुगतान कराने की मांग की है।

ग्राम पंचायत दुनिया के सचिव बुधार राम धुर्वे सहित और भी सचिव हैं, जिनका वेतन रोका गया है, ऐसे सचिव जो ग्राम पंचायत कार्यालय तो जाते हैं और जनपद पंचायत कार्यालय छुईखदान नहीं आते या कार्यालय प्रमुख से नहीं मिलते हैं, वैसे सचिव के वेतन रोका जाता है, बाकी सचिव का नियमित रूप से हर माह वेतन भुगतान किया जाता है।

केश्वरी देवांगन, सीईओ जनपद पंचायत छुईखदान

किसी नियमित सचिव का वेतन रोकना सीईओ के पदीय अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्यवाही है। यह मामला अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले कर्मचारी से जुड़ा है, सीईओ के द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वेतन रोकना गंभीर विषय है और इसकी उच्च स्तर पर जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए। सचिव का लंबित वेतन तत्काल जारी किया जाए, अन्यथा इस पूरे मामले की शिकायत उच्च स्तर पर की जाएगी।

सुधीर गोलछ, सभापति जनपद पंचायत छुईखदान

छुईखदान जनपद सीईओ के द्वारा अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर सचिव का वेतन जनपद पंचायत में रोके जाने की शिकायत प्राप्त हुई है, नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है प्रेम कुमार पटेल, सीईओ जिला पंचायत केसीजी

होण्डा कार मे बड़ी मात्रा में नगदी रकम परिवहन करते दो व्यक्तियों को चेकिंग के दौरान कोमाखान पुलिस ने पकड़ा

कार के अंदर 500-500 नोट का कुल 150 बंडल जुमला 75 लाख रुपये बरामद

महासमुन्द (समय दर्शन)। अवैध कारोबार पर महासमुन्द पुलिस की लगातार पैनी नजर बनी हुई है। इसी तारतम्य में बीते दिन वाहन सहित 75लाख रुपये बरामद हुआ है। वाहन में सवार व्यक्ति को नोटों के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने धारा 94 बी.एन.एस.एस का नोटिस किया गया जारी।

कार, मोबाइल एवं नगदी सहित जुमला जमी किमती 85,10,000.00 रुपये।

टेमरी नाका में दिनांक 16.03.2026 को वाहन चेकिंग के दौरान खरियार रोड उड़िसा की ओर से आ रही सफेद रंग की होण्डा कार क्रमांक ओडी 05 पीबी 2122 को रोककर चालक का नाम पता पूछने पर अपना नाम राजेन्द्र महानंद पिता बिडू महानंद उम्र 27 साल निवासी मुण्डापला थाना बेलपला जिला बलांगीर उड़िसा एवं चालक सीट के बाजू में बैठा व्यक्ति अपना नाम महाप्रज जैन पिता खेमचंद जैन उम्र 47 साल निवासी वार्ड 02 डेली मार्केट कांटाबांजी थाना कांटाबांजी जिला बलांगीर उड़िसा का होना बताया।

कार के बीच सीट में नीला रंग के बैग में रखे सामान के संबंध में पुछताछ करने पर महाप्रज जैन द्वारा सोना-चांदी खरीदी बिक्री का नगदी रकम 75 लाख रुपये को मनोहर मका एण्ड कंपनी एवं 60 ज्वेलर्स रायपुर को देने हेतु कांटाबांजी से रायपुर लेकर जाना



बताया।

उक्त वाहन में रखे नीला रंग की बैग का तलाशी लेने पर बैग के अंदर 500-500 नोट का बंडल प्रत्येक बंडल में 100-100 नोट कुल 150 बंडल जुमला 75 लाख रुपये रखे मिला। उक्त नोटों के संबंध में वैध कागजात पेघ करने धारा 94 बी.एन.एस.एस का नोटिस तामील किया गया। नोटिस में महाप्रज जैन द्वारा कोई कागजात नहीं होना।

लिखित में दिये जाने पर कार्यवाही करते हुए कुल संपत्ति कीमती 85,10,000 रुपये को जप्त किया गया है।

नगद राशि जिनसे जल की गई

01. महाप्रज जैन पिता खेमचंद जैन

बसना पुलिस ने मवेशी तस्करी के दो मामलों में की कार्यवाही

पिकअप वाहन सहित 6 भैंसे बरामद कर दो आरोपी गिरफ्तार

वहीं दूसरे मामले में पिकअप वाहन छोड़कर चालक मौके से फरार

बसना (समय दर्शन)। थाना बसना पुलिस ने मवेशी तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन से 6 भैंसे बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य मामले में पिकअप वाहन छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 15 मार्च 2026 को पिकअप वाहन में मवेशियों को भरकर तस्करी की जा रही है। सूचना पर पुलिस टीम ने ग्राम खटखटी से बसना की ओर आ रहे पिकअप वाहन क्रमांक एल 06 तल 5574 को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। वाहन की तलाशी लेने पर डाला में 03 बेल (लाल रंग) बिना चारा-पानी के रस्सी से बंधे मिले। पुलिस ने मोके पर पंचनामा कार्रवाई करते हुए मवेशियों व वाहन को जप्त कर लिया। इस मामले में चालक के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई है।

जप्त संपत्ति-

- 01- एक वाहन होण्डा कार ओडी 05 पीबी 2122 इस्तेमाली किमत 10 लाख रुपये।
- 02- 500 रुपये का कुल 150 बंडल जुमला 75 लाख रुपये।
- 03. एक नग मोबाइल किमत 10 हजार रुपये जुमला कुल जप्त संपत्ति कीमती 85,10,000 रुपये।



एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने ग्राम खटखटी की ओर से आ रही पिकअप वाहन क्रमांक एल 03.ए 6670 को रोककर जांच की। वाहन में 06 भैंसे भरे हुए पाए गए, जिन्हें आरोपियों द्वारा उड़िसा के कल्लखाने ले जाने की बात बताई गई। परिवहन के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर पुलिस ने भक्तान मेहेर उर्फ पिंटू (46 वर्ष) निवासी पटनागढ़, जिला बालांगीर (ओड़िशा) तथा जोगा कालिया

(23 वर्ष) निवासी सिंगामुंडाव, जिला बालांगीर (ओड़िशा) को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 06 भैंसे (कीमत लगभग 1,27,000 रुपये), एक महिंद्रा पिकअप वाहन (कीमत लगभग 5 लाख रुपये) तथा एक मोबाइल फोन जप्त किया है। आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 के तहत अपराध दर्ज कर आगे की विवेचना में लिया है।

सरपंच चंद्रिका साहू को मिली साहू समाज में अहम जिम्मेदारी

पाटन। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ द्वारा संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से नई नियुक्तियां की गई हैं। इसी क्रम में पाटन तहसील के ग्राम त्रीघाट निवासी श्रीमती चंद्रिका साहू को प्रदेश साहू संघ की कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया है। चंद्रिका साहू को यह जिम्मेदारी मिलने पर क्षेत्र के साहू समाज में खुशी का माहौल है। समाज के पदाधिकारियों एवं समाजजनों ने उन्हें बधाई देते हुए सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी हैं तथा आशा व्यक्त की है कि वे संगठन को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाएंगी।



क्रय समिति के अध्यक्ष डॉ. अलखराम वर्मा

आरटीआई से घोटाले का खुलासा : मेडिकल कॉलेज में डेढ़ करोड़ के टेंडर में गड़बड़ी, जेम पोर्टल दरकिनार कर मैनुअल दिया गया

महासमुन्द (समय दर्शन)। जिला मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज में सफ़ई और सुरक्षा गार्ड मूल्यांकन और वित्तीय बिड खोली से अधिक के टेंडर में बड़ी अनियमितता सामने आई है। वित्तीय अधिकार न होने के बावजूद डीन की अनुपस्थिति में क्रय समिति के पदाधिकारियों और कुछ लिपिकों ने मिलकर शासकीय जेम (बदरू) पोर्टल की अनिवार्य प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए मैनुअल टेंडर जारी कर दिया। इस पूरे मामले का समसमीखेज खुलासा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के जरिए हुआ है।

डीन की गैरमौजूदगी में पूरी हुई प्रक्रिया- आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार मेडिकल कॉलेज के डीन की गैरमौजूदगी में क्रय समिति के अध्यक्ष, सदस्यों और लिपिकों ने 15 और 20 जनवरी 2025 को टेंडर प्रक्रिया पूरी की। नियमों के अनुसार साफ-सफ़ाई और सुरक्षा व्यवस्था के

लिए टेंडर जेम पोर्टल के माध्यम से जारी होना था। दस्तावेज बताते हैं कि जेम पोर्टल पर तकनीकी व्यवस्था से जुड़े करीब डेढ़ करोड़ से अधिक के टेंडर में बड़ी अनियमितता सामने आई है। वित्तीय अधिकार न होने के बावजूद डीन की अनुपस्थिति में क्रय समिति के पदाधिकारियों और कुछ लिपिकों ने मिलकर शासकीय जेम (बदरू) पोर्टल की अनिवार्य प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए मैनुअल टेंडर जारी कर दिया। इस पूरे मामले का समसमीखेज खुलासा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के जरिए हुआ है।

ऑफलाइन जारी कर दिया ठेका- इसके बाद 26 मई और 26 जून 2025 को ऑफलाइन अनुबंध करते हुए ठेका जारी कर दिया गया। मेटास सिक्वोरिटी एंड फायर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को सफ़ाई व्यवस्था के लिए 75,09,007 रुपये, बुदेला सिक्वोरिटी एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को सुरक्षा व्यवस्था के लिए 75,09,007 रुपये इस प्रकार दोनों अनुबंधों की कुल राशि करीब पौने दो करोड़ रुपये तक पहुंचती है। **सुरक्षा निधि में भी गड़बड़ी के संकेत-** दस्तावेजों के अनुसार



मेटास कंपनी से 3 लाख 20 हजार रुपये का एफडीआर (सुरक्षा निधि) यूनिफन बैंक से जमा कराया गया, जबकि बुदेला सिक्वोरिटी के अनुबंध में 2 लाख 40 हजार रुपये सुरक्षा निधि का उल्लेख तो है, लेकिन उसका एफडीआर जमा होने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जेम पोर्टल से जानकारी भी गायब आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा जेम पोर्टल से संबंधित दस्तावेजों की

हार्ड कॉपी मांगी गई तो मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने लिखित में बताया कि कन्ट्रैक्ट ऑर्डर की कॉपी जेम पोर्टल में उपलब्ध नहीं है। इससे पूरे मामले में गंभीर संदेह और गहरा गया है। **नियमों का उल्लंघन कर जारी किया गया ऑफलाइन आदेश-** कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं विधायक द्वारिकाधीश यादव का कहना है कि यह काफी गंभीर मामला है। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर टेंडर



क्रय समिति के अध्यक्ष डॉ. अलखराम वर्मा

दिया गया है। कहीं भी क्रय नियम का पालन नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों के अनुसार सरकारी खरीद प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से ही की जानी चाहिए, लेकिन इस मामले में ऑफलाइन ठेका जारी कर दिया गया, जिससे चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की आशंका है। इस पूरे मामले को विधानसभा में रखा जाएगा और कार्रवाई की मांग की जाएगी। महासमुंद में सूचना का अधिकार में यह मामला आया है। जब यह मामला सदन में रख आया तो पूरे छत्तीसगढ़ के मामले

सामने आएंगे। **डीन ने कहा - नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई गई है-** मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. रेणुका गहाने का कहना है कि जेम पोर्टल से एल-वन के बाद नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई गई। एल-वन अनुमोदन के लिए आयुक्त को भेजा गया था। अनुमोदन के बाद अनुबंध किया गया। क्रय अधिकारी को क्रय आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। क्रय समिति के अध्यक्ष डॉ. अलखराम वर्मा, क्रय समिति के सदस्य, मेडिकल कॉलेज की क्रय समिति में शामिल सदस्य इस प्रकार हैं - अध्यक्ष एवं क्रय अधिकारी - डॉ. अलखराम वर्मा सदस्य - डॉ. बसंत महेश्वरी डॉ. ओंकार कश्यप डॉ. चंद्रपाल भगत डॉ. दिप्ती गौतम डॉ. शेष नारायण चंद्राकर डॉ. अनिल सिंह सहायक ग्रेड-2 - मुकेश देवांगन।

ई-केवायसी सही नहीं होने से प्रभावित हो रहा राशन वितरण, विपक्ष का वाक आउट

नेट नहीं पकड़ने से सड़क पर लगानी पड़ती है लाइन

रायपुर (समय दर्शन)। विधानसभा में आज कांग्रेस विधायकों ने ई-केवायसी प्रक्रिया सही नहीं होने के कारण दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में राशन वितरण व्यवस्था प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए खाद्य मंत्री दयालदास बघेल को घेरा और नारेबाजी करते हुए सदन से वाक आउट कर गए।

प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक दिलीप लहरिया का सवाल था कि क्या जिला बिलासपुर में ई-केवायसी अपडेट नहीं होने के कारण फरवरी, 2026 में राशन कार्डधारी सदस्यों का खाद्यान्न आबंटन रोक दिया गया है? यदि हां, तो खाद्यान्न आबंटन हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई? खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की ओर से जवाब आया कि बिलासपुर



जिले में ई-केवायसी हेतु शेष हितग्राहियों में से ऑफ लाइन उचित मूल्य दुकानों में संलग्न राशन कार्डों, एकल निराश्रित राशन कार्डों, निःशुक्रजन राशन कार्डों, गंभीर लाईलाज बीमारी वाले राशन कार्डों, नामिनी के माध्यम से खाद्यान्न उठाव करने वाले राशन कार्डों के सभी

हितग्राहियों को नियमित आबंटन जारी किया जा रहा है। वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17-07-2025 के अनुक्रम में हितग्राहियों का ई-केवायसी पूर्ण होने पर आबंटन जारी किया जाएगा। हितग्राहियों के ई-केवायसी हेतु उचित मूल्य दुकान में स्थापित ई-पॉस मशीन में प्रावधान दिया गया है। इसके साथ-साथ एंड्रायड

मोबाइल में 'मेरा ई-केवायसी' एप के माध्यम से फंस ई-केवायसी कर सकते हैं। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा कि ऐसे कितने ही स्थान हैं जहां जनवरी, फरवरी का राशन नहीं मिला। मार्च में केवायसी हुआ। क्या जनवरी, फरवरी एवं मार्च का एक साथ राशन प्रदान करेंगे? इस पर मंत्री की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं आया, जिस पर विरोध दर्ज कराते हुए विपक्षी विधायकगण शोर मचाने लगे।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैं विधायक जनक ध्रुव के बिन्दानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में गया था। वहां के खरदा गांव में मैंने देखा कि लोग सड़क पर लाइन लगाकर खड़े हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि राशन दुकान में नेट नहीं पकड़ता। यही कारण है लोगों

को सड़क पर केवायसी कराना पड़ रहा है। एक आदमी के काम में पांच मिनट लग रहे थे। यह स्थिति बिन्दानवागढ़ ही नहीं बल्कि बस्तर तथा और कई अन्य स्थानों की है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को लाइन में देखा जा सकता है। यह संख्या लाखों में है। नेट नहीं चल पाने के कारण ठीक तरीके से केवायसी नहीं हो पा रहा उस पर क्या व्यवस्था देंगे? मंत्री ने कहा कि ई-केवायसी बराबर हो रहा है। पिछले महीनों में व्यवस्था सुधरी है। मंत्री की तरफसे ठोस जवाब नहीं आने का आरोप लगाते हुए विपक्षी विधायक शोर मचाने लगे। विरोध दर्ज कराने का क्रम शोर शराबे तक ही सीमित नहीं रहा। कुछ देर बाद सारे विपक्षी विधायकगण नारेबाजी करते हुए सदन से वाक आउट कर गए।

बृजमोहन अग्रवाल की अनुशंसा से बलौदा बाजार-भाटापारा में तेज़ होगा विकास

रायपुर :- रायपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री बृजमोहन अग्रवाल के सतत प्रयासों से बलौदा बाजार और भाटापारा विधानसभा क्षेत्र को विकास की एक और बड़ी सीमा मिली है। सांसद श्री अग्रवाल की अनुशंसा पर जिला खनिज न्यास निधि (DMF) से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 5.99 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न जनहितैषी विकास कार्यों के लिए स्वीकृत प्रदान कर दी गई है। इस राशि से बलौदा बाजार और भाटापारा जिले के 25 आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनवाड़ी केन्द्र बनाया जाएगा, साथ ही पाटन में जल संचयन हेतु अमृत सरोवर के तर्ज पर तालाब पुनरुद्धार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के विभिन्न वार्डों एवं ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए सीसी रोड निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, आहता निर्माण, पेवर ब्लॉक निर्माण, स्ट्रीट लाइट की स्थापना तथा स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। इन विकास कार्यों के पूरा होने से स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।



सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्र के हर गांव और हर वार्ड तक विकास की रोशनी पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं को अनुरूप विकास कार्यों को गति देने के लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं और आगे भी इसी प्रतिबद्धता के साथ क्षेत्र के विकास के लिए काम करते रहेंगे। श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में केंद्र सरकार की

नशेड़ी वाहन चालकों के विरुद्ध रायपुर पुलिस की कार्यवाही जारी

रायपुर। रात्रि को फंसे 132 नशेड़ी वाहन चालक ड्रक एंड ड्राइव कार्यवाही का उद्देश्य सड़क दुर्घटना में कमी लाना, जान माल की रक्षा करना, सड़क में चलते समय अनुशासन लाना है। रायपुर शहर में सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है। डॉ. संजीव शुक्ला पुलिस कमिश्नर और श्री विकास कुमार पुलिस उपायुक्त, यातायात एवं प्रोटोकॉल के निर्देशानुसार शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है और वाहन ड्राइवर अपने जीवन के साथ-साथ दूसरे के जीवन के लिए भी खतरा पैदा करता है।



वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष जनवरी से आज तक लगभग 1100 नशेड़ी वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है, जिन्हें नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया।

इस अभियान के अंतर्गत दिनांक 14 मार्च 2026 की रात्रि में एडिशनल डीसीपी श्री विवेक शुक्ला के नेतृत्व में शहर के आठ स्थानों पर यातायात थाना प्रभारी एवं यातायात पुलिस स्टॉफ के साथ विशेष चेकिंग अभियान

चलाया गया। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाते हुए कुल 132 वाहन चालकों को पकड़ा गया, जिनके विरुद्ध चालान की कार्यवाही कर उच्च सोमवार को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

लोगों में भ्रांति है कि पुलिस कोई टारगेट पूरा करने अभियान चलाती है, जबकि यातायात पुलिस का यह अभियान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि शराब पीकर वाहन चलाना न केवल कानून अपराध है, बल्कि यह स्वयं तथा अन्य लोगों के जीवन के लिए गंभीर खतरा भी है, अतः इस पर ज़ोरों टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी।

आम नागरिकों से अपील - यातायात पुलिस रायपुर सभी वाहन चालकों एवं नागरिकों से अपील करती है कि वे सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभायें।

'मरीजों की सेहत से समझौता नहीं' - स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल

रायपुर। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रविवार को शासकीय सिविल अस्पताल मनेन्द्रगढ़ का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना तथा उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।



निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में उपचार व्यवस्था, दवाइयों की उपलब्धता, साफ-सफाई तथा अन्य व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने डॉक्टरों एवं अस्पताल प्रबंधन से आवश्यक जानकारी लेते हुए मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया कि मरीजों को समय पर इलाज

व्यवस्थाओं की जानकारी ली और साफ-सफाई को लेकर संतोष व्यक्त किया।

सीएचएमओ डॉ. खरे ने बताया कि अस्पताल परिसर में अनावश्यक रूप से आने वाले अवांछनीय तत्वों की रोकथाम के लिए सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। ऐसे लोगों पर निगरानी रखने के लिए अस्पताल में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की गई है, जो दो शिफ्टों में तैनात रहते हैं। उन्होंने बताया कि भविष्य में जब मेडिकल कॉलेज प्रारंभ होगा, तब सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाएगा। इस दौरान सीएचएमओ डॉ. अविनाश खरे, स्विनल तिवारी, मंडल अध्यक्ष रवि वर्मा सहित अस्पताल के चिकित्सक, अधिकारी एवं स्टाफ उपस्थित रहे।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव ने नेशनल ट्राइबल गेम्स की तैयारियों की समीक्षा की अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करें सभी खेल स्थलों को - श्री यशवंत कुमार

रायपुर। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार ने छत्तीसगढ़ की मेजबानी में देश में पहली बार हो रहे खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने आज रायपुर के साईंस कॉलेज परिसर स्थित खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालनालय में आयोजित बैठक में आयोजन की व्यवस्थाओं में लगे विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने पर्याप्त समय रहते सभी इंतजाम पुख्ता रूप से सुनिश्चित करने को कहा।



खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव ने नेशनल ट्राइबल गेम्स की तैयारियों की समीक्षा की - खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार ने बैठक में कहा कि खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स राष्ट्रीय महत्व और छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठा से जुड़ा आयोजन है। इससे संबंधित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त, पुख्ता एवं चौक-चोबंद

होने चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को कार्यों में तेजी लाते हुए पर्याप्त समय रहते सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयोजन के लिए चिन्हांकित सभी खेल स्थलों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करने को कहा।

विभागीय सचिव श्री कुमार ने खेल मैदानों, खिलाड़ियों के उठरने की जगहों, विमानतल और रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में स्टॉफ तैनात करने के निर्देश दिए, ताकि आयोजन में भाग लेने पहुंचने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं अधिकारियों को किसी भी तरह की

परेशानी न हो। उन्होंने संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के अधिकारियों को ट्राइबल गेम्स में हिस्सेदारी के लिए विभिन्न राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले प्रतिभागियों को यहां की संस्कृति, पुरातत्व एवं कला की जानकारी देने के साथ ही पर्यटन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने को कहा। श्री कुमार ने आयोजन में विभिन्न भाषाओं वाले राज्यों की भागीदारी को देखते हुए उन भाषाओं के जानकार अधिकारियों-कर्मचारियों को वेतलफिंग और तीरंदाजी की स्पर्धाएं संचालक श्रीमती तुनजा सलाम और उप संचालक श्रीमती रश्मि ठाकुर सहित रायपुर जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, परिवहन, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, जनसंपर्क, स्वास्थ्य विभाग, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी बैठक में मौजूद थे। अंबिकापुर और जगदलपुर के अधिकारी

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में शामिल हुए।

रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक नेशनल ट्राइबल गेम्स-छत्तीसगढ़ की मेजबानी में रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक नेशनल ट्राइबल गेम्स की 7 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इसमें दो अन्य खेलों, कबड्डी और मलखंब को डेमो के रूप में शामिल किया गया है। हॉकी, फुटबॉल, तैराकी, वेतलफिंग और तीरंदाजी की स्पर्धाएं रायपुर में होंगी। वहीं जगदलपुर में एथलेटिक्स और अंबिकापुर में कुश्ती की प्रतियोगिताएं होंगी। डेमो खेलों में कबड्डी का रायपुर में और मलखंब का प्रदर्शन अंबिकापुर में किया जाएगा। देश में पहली बार हो रहे खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स में 30 राज्यों के 2500 खिलाड़ी, प्रशिक्षक एवं अधिकारी शामिल होंगे।

संक्षिप्त समाचार

नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। थाना आरंग पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरोपी सुनील कुर् (23 वर्ष) और कैलाश कुर् (22 वर्ष), निवासी सतनामी पारा नारा, थाना आरंग, जिला रायपुर, पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए। यह घटना दिनांक 11.03.2026 की दरम्यानी रात लगभग 03:00 से 04:00 बजे के बीच ग्राम बरछा में हुई थी। पीड़िता की 15 वर्षीय बेटी को आरोपियों ने बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की। इस गंभीर मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। जांच के दौरान, पुलिस ने दिनांक 13.03.2026 को पीड़िता को सुरक्षित बरामद किया। पीड़िता का कथन महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष दर्ज किया गया, जिसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ अपराध क्र. 153/2026 के तहत धारा 137(2), 65(1), 87, 3(5) बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा 06 के तहत मामला दर्ज किया गया। पीड़िता के सुरक्षित बरामद होने के बाद आरोपी सुनील कुर् और कैलाश कुर् को गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने आरोपियों को केंद्रीय जेल रायपुर में भेजने का आदेश दिया।

हास्पिटल सेक्टर सहित चेरिटेबल ट्रस्ट में पंजीकृत संस्थाओं पर सुप्रीम कोर्ट 17 एवं 18 को करेगी समीक्षा

रायपुर। आज से 48 वर्ष से पहले भारत के प्रख्यात न्यायाविद जस्टिस व्हीआर कृष्णा अय्यर द्वारा बैंगलोर वाटर सल्लाई मामले को लेकर किन संस्थाओं को औद्योगिक संस्थाओं का दर्जा दिया जाए और किन्हें इससे बाहर रखा जाए विषय पर लंबा चौड़ा निर्णय आया था जिसमें चेरिटेबल ट्रस्ट में दर्ज संस्थाओं यथा हास्पिटल सेक्टर को भी उद्योग श्रेणी के मामलों से अलग रखा गया था ज्ञातव्य है कि छग सहित संपूर्ण देश में हास्पिटल सेक्टर में इन दिनों जिस तरीके से वसूली की जा रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी ध्यान गया है। चेरिटेबल ट्रस्ट में दर्ज अस्पतालों में भी निशुल्क इलाज की व्यवस्था पहली शर्त होने के बावजूद भी गायब है। बीमारी में छोटे स्वरूप को बड़ा स्वरूप देने के लिए ज्यादा कमाई की जा रही है। जिसकी वजह से आम आदमी को कमर टूट गई है। 48 साल बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में नौ जजों की संविधान पीठ 17 एवं 18 मार्च को विस्तृत समीक्षा करेगी। इसमें हास्पिटल सेक्टर को भी धंधे में परिभाषित किये जाने की संभावना है। जस्टिस सूर्यकांत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के अनेक जजों को देश के अनेक हिस्सों से आडियो रिकार्डिंग वीडियो रिकार्डिंग एवं दस्तावेजी साक्ष्य कुछ बड़े अस्पतालों के खिलाफ मिले हैं जिनमें कम समयवाधि में भर्ती मरीजों से 20 से 25 लाख रुपये की वसूली की गई है जिन प्रभावितों से वसूली की गई है। यह ज्यादातर निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं। उल्लेखनीय है कि अनेक आरटीआई संस्थाओं द्वारा भी इस संबंध में मेडिकल कॉन्सिल ऑफ इंडिया जिसे आप नेशनल कॉन्सिल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है में सबूतों के साथ प्राइवेट सेक्टर के विशेषकर कार्पोरेट सेक्टर के अस्पतालों द्वारा मनमाजी वसूली पर नियंत्रण हेतु कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है किंतु अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अस्पतालों के दशा और दिशा बदलकर धंधे के रूप में परिभाषित होने की पूर्ण संभावना है। धंधे में नामित होते ही मान्यता प्राप्त अस्पतालों पर प्रदेश सरकारों को फिर से नये नियम बनाने होंगे। साथ ही नर्सिंग होम एक्ट में दर्ज धाराओं को भी परिवर्तित करना होगा।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से लाभान्वित हुई निशि श्रीवास

रायपुर। खैरागढ़, छुईखदान गंडई जिले के ग्राम टेकापार कला की निवासी श्रीमती निशि श्रीवास ने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट का सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित कर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्राप्त किया है। सोलर प्लांट लगवाने से पहले उनके घर का बिजली बिल लगभग 7500 प्रतिमाह आता था, जिससे घरेलू खर्चों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था। योजना के अंतर्गत सोलर पैनाल स्थापित होने के बाद अब उनकी स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है। सोलर सिस्टम से बिजली का उत्पादन होने के कारण उनका बिजली बिल अब शून्य (0) हो गया है। हाल ही में उनके सोलर प्लांट से कुल 282 यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ, जिस पर उन्हें 7474 का सोलर रिबेट भी प्राप्त हुआ। श्रीमती निशि श्रीवास का कहना है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से न केवल बिजली बिल में राहत मिली है, बल्कि यह स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अब वे अपना गांव तथा आसपास के लोगों को भी इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

रायपुर रेलवे स्टेशन के कैफे में दो गुटों के बीच मारपीट

रायपुर। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन परिसर स्थित एक कैफे में शनिवार शाम दो गुटों के बीच जमकर मारपीट की घटना सामने आई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम करीब 5 बजे कुछ युवक कैफे में पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि वे नशे की हालत में थे और वहां मौजूद कुछ लड़कियों पर कथित रूप से अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। इस बात का विरोध करने पर वहां मौजूद अन्य युवकों के साथ उनका विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लात-पूंसे मार रहे हैं और कैफे में रखी कुर्सियां व अन्य सामान भी एक-दूसरे पर फेंके जा रहे हैं। अचानक हुए इस हंगामे से कैफे में अग्न्या-तफरी मच गई और वहां मौजूद कई लोग डर के कारण बाहर निकल गए। यह घटना रायपुर रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाना क्षेत्र की बवाई जा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद जीआरपी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर संबंधित युवकों को पहचान की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की घटनाएं सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकती हैं। वहीं कैफे के संचालक और कर्मचारियों ने भी घटना को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि इससे उनके व्यवसाय और सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। फिलहाल पुलिस ने कैफे में लगे सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

संपादकीय



नई व्यवस्था बनने की आशाएं धूमिल

नेताओं के अवसरवाद तथा आर्थिक समस्याओं से त्रस्त नौजवानों ने कुछ नया बनाने की इच्छा के साथ तत्कालीन सरकार को उखाड़ फेंका था। लेकिन उसके बाद अब लोगों के पास जो विकल्प हैं, उनसे नई व्यवस्था बनने की आशाएं धूमिल ही हैं। पिछले साल सितंबर में हुए जेन-जी विद्रोह से नेपाल में आया बदलाव कितना टिकाऊ साबित हुआ, यह गुरुवार को होने वाले मतदान के परिणाम से जाहिर होगा। नेपाल के एक करोड़ 90 लाख मतदाता 275 सदस्यों की प्रतिनिधि सभा को चुनने के लिए मतदान करेंगे। नेपाल की चुनाव प्रणाली के मुताबिक 165 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत चुने जाते हैं। बाकी 110 सीटें विभिन्न पार्टियों को उन्हें मिले मत प्रतिशत के अनुपात में आवंटित की जाती हैं। जेन-जी विद्रोह का प्रमुख कारण राजनीतिक दलों की सत्ता लिप्सा, वर्षों से जारी उनका अवसरवाद, और रजनीतावार बलाया गया है। आलीशान जिंदगी थी। बेरोजगारी तथा आर्थिक समस्याओं से त्रस्त नौजवानों ने कुछ नया बनाने की इच्छा के साथ तत्कालीन सरकार को हिसक ढंग से उखाड़ फेंका। लेकिन विडंबना यह है कि उसके बाद अब लोगों के पास जो विकल्प हैं, उनसे नई व्यवस्था बनने की आशाएं धूमिल ही हैं। लोगों के सामने नए विकल्प के तौर पर उज्यालो नेपाल पार्टी अकेला नया दल है, लेकिन उसकी संभावनाएं ज्यादा उज्वल नहीं मानी जा रही हैं। नयेपन का अहसास कराने वाला एक अन्य दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) है, जिसका उदय पिछले संसदीय चुनाव के समय हुआ था। रैपर और काठमांडू के बहुचर्चित मेयर बालेन शाह इसी दल में शामिल होकर प्रधानमंत्री के दावेदार के बतौर चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें जेन-जी का फिय उम्मीदवार बताया गया है। बाकी विकल्प वही पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूएमएल), नेपाली कांग्रेस, और कई कम्युनिस्ट गुटों के विलय से पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के नेतृत्व में बनी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी हैं। पारंपरिक समर्थन आधार और चुनाव मशीनरी के लिहाज से ये तीनों पार्टियां अभी भी मजबूती के साथ मैदान में हैं। वैसे युवाओं के समर्थन से आरएसपी जीत की ओर बढ़ सकती है। मगर यह पार्टी किसी बुनियादी परिवर्तन का माध्यम बनेगी, अपने कार्यक्रम एवं चुनाव घोषणापत्र से ऐसी कोई उम्मीद वह नहीं जगा पाई है। यानी नेपाल में किसी गुणात्मक परिवर्तन के संकेत कम ही हैं। मात्रात्मक बदलाव भी आएगा, इसकी उम्मीद बहुत बलवान नहीं है।

निवारक स्वास्थ्य देखभाल में अग्रणी भूमिका निभा रहा है योग

प्रतापराव जाधव द्वारा

बीते दशक में योग को केवल पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति के रूप में ही नहीं सराहा गया, बल्कि उसे उत रोचकर रूप से स्वास्थ्य और कल्याण के लिए साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण के रूप में भी पहचाना जाने लगा है। वैज्ञानिक अनुसंधान, डिजिटल नवाचार और वैश्विक सहयोग अब हमें योग को केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत ही नहीं, बल्कि एक सरक जैन-स्वास्थ्य हस्तक्षेप समझने में भी मदद कर रहे हैं। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था न (एमडीएनआईवाई) को पारंपरिक चिकित्सा (योग) के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया है और योग अनुसंधान में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका और भी मजबूती प्रदान करते हुए वर्ष 2025-2029 के लिए इसे फिर से निमित्त किया गया है। यह पहचान गैर-संचारी रोग (एनसीडी) के लिए साक्ष्य-आधारित योग हस्तक्षेपों को बढ़ावा देने में सफल न की बढ़ती भूमिका को दिखाती है। इस पहल के प्रमुख साझेदारों में आयुष मंत्रालय, एम्सा दिल्ली, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, और इंटीग्रेटेड यूएफ ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, दिल्ली शामिल हैं। इन सहयोगों के माध्यम से केंद्र मधुमेह, मोटापा और तनाव से संबंधित विकारों जैसे गैर-संचारी रोगों के लिए योग-आधारित हस्तक्षेपों पर तकनीकी दिशानिर्देश विकसित कर रहा है और अनुसंधान को आगे बढ़ा रहा है। इन प्रयासों में अंतरराष्ट्रीय संगठन भी साझेदारी कर रहे हैं, जिससे योग की वैज्ञानिक आधारशिला और मजबूत हो रही है तथा निवारक स्वास्थ्य देखभाल के लिए व्यापक रूप से लागू किए जा सकने वाले, किफायती और साक्ष्य-समर्थित प्रभावी साधन के तौर पर योग की क्षमता प्रदर्शित हो रही है। संस्थागत स्तर पर एमडीएनआईवाई योग की वैज्ञानिक आधारशिला को मजबूती प्रदान करना जारी रखे हुए है। शरीर क्रिया विज्ञान, जैव रसायन, बायोमैकेनिक्स और मनोविज्ञान की अनुसंधान प्रयोगशालाओं के माध्यम से यह संस्थान योग के मनो-शारीरिक और जैव-रासायनिक प्रभावों, उम्र बढ़ने में इसकी भूमिका तथा जीवनशैली से जुड़े विकारों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करता है। यह कार्य पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ जोड़ने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है डिजिटल प्लेटरफॉर्मों ने योग की पहुंच को और अधिक बढ़ाया है, जिससे साक्ष्य-आधारित पद्धतियों सीधे लोगों के दैनिक जीवन के हिस्सा बन रही हैं। एम-योग मोबाइल एप्लिकेशन और वाई-ब्रेक प्रोटोकॉल जैसे प्रयास यह दिखाते हैं कि योग की प्रामाणिकता और चिकित्सकीय महत्व बनाए रखते हुए उसे बड़े स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से विकसित किए गए एम-योग प्लेटफॉर्म पर 1.1 लाख से अधिक डाउनलोड दर्ज किए जा चुके हैं, जो सुलभ डिजिटल वेबनेस टूल्स में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। वहीं कार्यस्थल योग कार्यक्रम वाई-ब्रेक जो काफे के दौरान 5-10 मिनट का सरल योग ब्रेक है — से अब तक 33 लाख से अधिक सरकारी अधिकारियों को लाभ मिल चुका है। इन पहलों से प्राप्त अनुसंधान निष्कर्ष और सहभागिता विश्लेषण अत्यंत उसाहजनक हैं। वाई-ब्रेक अभ्यास से कुछ ही सप्ताहों में अनुभूत तनाव में लगभग 20 प्रतिशत तक कमी देखी गई है। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि इससे मानसिक सतर्कता, भावनात्मक दृढ़ता और निर्णय-क्षमता में सुधार होता है। इसके साथ-साथ कार्टीसोल स्तर जैसे शारीरिक संकेतकों में भी सकारात्मक परिवर्तन पाए गए हैं।

तेल-गैस संकट के बीच सेंसेक्स का गिरना क्या अर्थतंत्र में महासंकट के संकेत?

सौरभ वर्णाय

वैश्विक अर्थव्यवस्था में जब भी ऊर्जा संकट गहराता है, उसका सीधा असर वित्तीय बाजारों और आम लोगों की जेब पर दिखाई देता है। हाल के दिनों में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी तथा आपूर्ति को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच भारतीय शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक गिरावट की ओर गया है। यह गिरावट केवल बाजार की सामान्य हलचल नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के सामने खड़े संभावित बड़े संकट का संकेत भी हो सकती है। वहीं जब में इस लेख को लिख रहा हूँ तो सेंसेक्स और निफ्टी काफ़ी हद तक गिर चुका है। ऐसे में सरकार के कहने के बावजूद जनमानस इस युद्ध के बीच ऊर्जा का भंडार भरकर रखना चाहता है। यह युद्ध क्या पटकथा लिखेगा, कोई नहीं जानता क्योंकि रुस-युक्रेन युद्ध भी अभी तक समाप्त नहीं हुआ।

भारत जैसे देश की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित तेल और गैस पर निर्भर है। जब वैश्विक स्तर पर तेल-गैस की कीमतें बढ़ती हैं या आपूर्ति बाधित होती है, तो उसका असर सीधे महंगाई, उत्पादन लागत और व्यापार संतुलन पर पड़ता है। उद्योगों की लागत बढ़ती है, परिवहन महंगा होता है और अंततः इसका बोझ आम उपभोक्ता तक पहुंचता है। निवेशकों को भी यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में कंपनियों के मुनाफे पर दबाव बढ़ सकता है। शेयर बाजार का गिरना इसी चिंता का प्रतिबिंब है। निवेशक भविष्य की आशाओं को देखते हुए बाजार से पैसा निकालने लगते हैं। विदेशी निवेशक भी जोखिम से बचने के लिए उभरते बाजारों से पूंजी निकालते हैं जिससे बाजार में गिरावट और तेज हो जाती है। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास की गति पर पड़ सकता है।

ऊर्जा संकट का दूसरा पहलू राजकोषीय दबाव भी है। सरकार को महंगाई नियंत्रित करने के लिए करों में कटौती, सब्सिडी या अन्य राहत उपाय देने पड़ सकते हैं। इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता है। साथ ही यदि आयात बिल बढ़ता है तो चालू खाते का घाटा भी बढ़ सकता है जो आर्थिक स्थिरता के लिए चुनौती बन जाते हैं हालांकि यह भी सच है कि शेयर बाजार हमेशा दीर्घकालिक आर्थिक स्थिति का सटीक दर्पण नहीं होता। कई बार वैश्विक परिस्थितियों, भू-राजनीतिक तनाव या निवेशकों की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया से भी बाजार अचानक गिर सकता है। इसलिए सेंसेक्स की गिरावट को तुरंत महा संकट मान लेना भी उचित नहीं होगा लेकिन इसे एक चेतावनी संकेत जरूर माना जाना चाहिए।



ऐसे समय में सरकार और नीति-निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की है। देश को तेल-गैस के आयात पर निर्भरता कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और रणनीतिक भंडार बढ़ाने जैसी नीतियों पर तेजी से काम करना होगा। साथ ही आर्थिक सुधारों और निवेश को बढ़ावा देकर बाजार का भरोसा बनाए रखना भी जरूरी है।

अंततः कहा जा सकता है कि तेल-गैस संकट के बीच सेंसेक्स की गिरावट केवल बाजार की घटना नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी चुनौतियों की याद दिलाती है। यदि समय रहते ठोस कदम उठाए जाएं तो यह संकट अवसर में भी बदल सकता है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो इसके गंभीर आर्थिक परिणाम सामने आ सकते हैं।

निवेशक दोहरी दुविधा में- वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिस्थितियों के बीच आज निवेशक एक कठिन दौर से गुजर रहा है। बाजार में अनिश्चितता, अंतरराष्ट्रीय तनाव और महंगाई के दबाव ने निवेशकों को दोहरी दुविधा में डाल दिया है। एक ओर शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षित निवेश विकल्प भी अपेक्षित रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे माहौल में यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि निवेशक अपने धन को कहाँ और कैसे सुरक्षित रखें।

हाल के समय में वैश्विक स्तर पर कई घटनाएँ आर्थिक बाजारों को प्रभावित कर रही हैं। तेल-गैस की कीमतों में अस्थिरता, अंतरराष्ट्रीय संघर्ष और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों में बदलाव का असर भारत सहित दुनिया के शेयर बाजारों पर दिखाई दे रहा है। जब भी वैश्विक स्तर पर संकट गहराता है, निवेशक जोखिम से बचने के लिए सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करते हैं लेकिन

वर्तमान स्थिति में सुरक्षित निवेश भी बहुत आकर्षक नहीं दिख रहा। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर भी निवेशकों के सामने कई सवाल खड़े हैं। महंगाई की दर में उतार-चढ़ाव, ब्याज दरों की अनिश्चितता और कंपनियों के भविष्य को लेकर आशाएँ निवेशकों को निर्णय लेने में कठिनाई पैदा कर रही हैं। शेयर बाजार में निवेश करने पर जोखिम अधिक है, जबकि बैंक जमा या अन्य सुरक्षित विकल्पों में रिटर्न सीमित है। यही कारण है कि निवेशक समझ नहीं पा रहे कि जोखिम उठाकर बाजार में बने रहें या सुरक्षित विकल्पों में पैसा लगाएँ।

निवेशकों की यह दुविधा केवल आर्थिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। बाजार की अस्थिरता के कारण कई छोटे निवेशक घबराकर अपने निवेश को निकाल लेते हैं, जिससे बाजार में और अधिक गिरावट देखने को मिलती है। वहीं कुछ अनुभवी निवेशक इसे अवसर के रूप में देखते हैं और गिरते बाजार में निवेश बढ़ाते हैं।

ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है संतुलित और दीर्घकालिक दृष्टिकोण। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशकों को घबराहट में निर्णय लेने के बजाय अपने निवेश को विविध क्षेत्रों में बांटना चाहिए और लंबी अवधि की रणनीति अपनानी चाहिए। इससे जोखिम कम किया जा सकता है और बाजार की अस्थिरता का प्रभाव भी सीमित किया जा सकता है।

सरकार और नियामक संस्थाओं की भी जिम्मेदारी है कि वे आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ। पारदर्शी नीतियाँ, निवेश के अनुकूल वातावरण और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देकर निवेशकों का भरोसा मजबूत किया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय निवेशकों के लिए परीक्षा का दौर है। दोहरी

दुविधा के बीच सही निर्णय वही होगा जो धैर्य, समझ और दीर्घकालिक सोच पर आधारित हो। अगर निवेशक संतुलित रणनीति अपनाते हैं, तो अस्थिर बाजार भी भविष्य के अवसरों में बदल सकता है।

तेल-गैस संकट से कैसे मिले निजात?— विश्व राजनीति और ऊर्जा बाज़ार में बढ़ती अनिश्चितता ने एक बार फिर तेल-गैस संकट की आशंका को गहरा कर दिया है। मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव, आपूर्ति में रुकावट और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कीमतों के उतार-चढ़ाव का सीधा असर भारत जैसे आयात-निर्भर देश पर पड़ता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए जब भी वैश्विक स्तर पर संकट पैदा होता है, उसका दबाव देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग और आम उपभोक्ता पर साफ़ दिखाई देता है तेल और गैस केवल ईंधन नहीं, बल्कि आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। परिवहन, बिजली उत्पादन, उद्योग और घरेलू उपयोग—हर क्षेत्र इन पर निर्भर है। जब इनकी कीमतें बढ़ती हैं या आपूर्ति कम होती है, तो महंगाई बढ़ती है, उत्पादन लागत बढ़ती है और आर्थिक विकास की गति भी प्रभावित होती है। इसलिए यह केवल ऊर्जा संकट नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक चुनौती भी बन जाता है।

इस संकट से निपटने के लिए सरकार को बहुस्तरीय रणनीति अपनानी होगी। सबसे पहले, ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण जरूरी है। भारत को केवल कुछ सीमित देशों पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग क्षेत्रों से तेल और गैस को आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। दीर्घकालिक समझौते और रणनीतिक भंडारण भी आपूर्ति सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम वैकल्पिक और नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन जैसे स्रोत भविष्य में तेल-गैस पर निर्भरता कम कर सकते हैं। भारत ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं लेकिन इसे और तेज़ी से बढ़ाने की आवश्यकता है। तीसरा, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना भी जरूरी है। उद्योगों, उर्जाओं और घरेलू उपयोग में ऊर्जा की बचत से खपत कम की जा सकती है। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन और सार्वजनिक परिवहन का विस्तार भी तेल की मांग घटाने में मदद कर सकता है। तेल-गैस संकट हमें यह याद दिलाता है कि ऊर्जा सुरक्षा केवल आयात से नहीं बल्कि दीर्घकालिक नीति, तकनीकी नवाचार और आत्मनिर्भरता से ही सुनिश्चित हो सकती है। यदि भारत समय रहते सही कदम उठाता है, तो वह न केवल इस संकट से उबर सकता है बल्कि भविष्य की ऊर्जा चुनौतियों का भी मजबूती से सामना कर सकता है।

नेपाल में महिला दिवस पर चुनावी गिफ्ट

डॉ. सुधीर सक्सेना

नेपाल में बिना होहल्ले और शोरशराबे के चुनाव सम्पन्न हो गये। ईरान-इरायल जंग के दरम्यान हुये इस चुनाव को और लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं गया, किंतु महिला दिवस पर आये नतीजों ने छोटे मुल्क में बड़ी इबारतें लिख दीं। मतदाताओं ने वाम और दक्षिण को धता बताया, राजशाही के समर्थकों को ठेगा दिखाया और फकत चार साल पहले वजूद में आई पार्टी - राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को प्रचंड जनदेश प्रदान किया। जनदेश के फलस्वरूप 35 वर्षीय बालेन शाह नेपाल के युवतम प्रधानमंत्री होंगे। इस पद तक पहुँचे वह पहले मधेशी और पहले बौद्ध मतावलंबी

थी हैं। इस दूरगामी महत्त्व के चुनाव की एक और खासियत रही कि आरएसपी की 16 प्रत्याशियों में से 13 विजयी रहीं। बिना सक्ष का इस महिला दिवस पर नेपाली मतदाताओं की खूबसूरत और काबिले तारीफ गिफ्ट माना जा सकता है।

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) ने महिला उम्मीदवारों की सफलता मत एक मील का पत्थर हासिल किया है, जिसमें उसकी 16 में से 13 महिला उम्मीदवार विजयी हुई हैं। ज़्यादातर विजेताओं ने भारी अंतर से अपनी सीटें हासिल कीं, जो पार्टी की महिला नेताओं के लिए समर्थन की एक मजबूत लहर को दिखाता है हालांकि, पार्टी को तीन हार का सामना करना पड़ा। बिनीता

कटायत जुमला में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के ज्ञानेंद्र शाही से हार गई; सरिन तमांग को सुनसरी-1 में श्रम संस्कृति पार्टी के हरका राज राय ने हराया; और तशी ल्हान्जोम हुमाल में चौथे स्थान पर रहे। रूतू दर्शना ने काठमांडू-1 में पार्टी का खता खोला, ललितपुर-3 में, तोसिमा कार्की ने लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल किया। सविता गौतम, जिन्होंने 2022 के चुनाव में काठमांडू-2 का प्रतिनिधित्व किया था, ने सफलतापूर्वक अपना निर्वाचन क्षेत्र चितवन-3 में स्थानांतरित कर दिया। उन्हें 59,277 वोट मिले, जिससे उन्होंने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की उम्मीदवार रेणु दहाल, जो भरतपुर मेट्रोपालिटन सिटी की पूर्व मेयर

थीं, को भारी हार का सामना करना पड़ा। रेणु दाहाल पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड की बेटी हैं। मोरंग-6 में, काठमांडू यूनिवर्सिटी से एमबीए ग्रेजुएट रबीना आचार्य ने 55,513 वोटों के साथ जबरदस्त जीत हासिल की। और दक्षिण में मोरंग-5 में, पब्लिक हेल्थ ग्रेजुएट और पहले हेल्थ वॉलंटियर रहीं आशा झा ने 20,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। झापा में, ऋक्म ने दो जैत दर्ज कीं। निशा डगंगी (झापा-1) ने 45,680 वोट हासिल किए, पूर्व डिप्टी स्प्रीकर इंदिरा राणा मगर (झापा-2) को 60,110 वोट मिले। सरलाही-1 में, नितिमा भंडारी कार्की ने 44,181 वोटों के साथ जीत हासिल की, एक सफल एग्रीकल्चरल

एण्ट्रप्रेन्योर कोमल ग्यावली कैलाली-1 से 17,862 वोटों के साथ चुनी गईं। सोशल वर्कर बीना गुरुंग ने 37,750 वोट हासिल किए और कास्की-3 में कांग्रेस उम्मीदवार मनोज गुरुंग को 24,970 वोटों के अंतर से हराया। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आशिका तामांग 39,128 वोटों के साथ संसद में पहुंचीं, उन्होंने धार्दिंग-1 में यूएमएल के पुराने नेताओं भूमि प्रसाद पौड्याल और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के राजेंद्र प्रसाद पांडे को हराया। ससरी-1 से छत्तीस साल की पुष्पा कुमारी चौधरी ने 38,195 वोटों के साथ बड़ी जीत हासिल की। महाोतरी-4 में, गौरी कुमारी ने 30,132 वोट हासिल किए।

अनुशासन या अपमान? शिक्षा व्यवस्था पर उठते सवाल

डॉ. सत्यवान सौरभ

हाल के दिनों में विद्यालय में छात्राओं को मुर्गा बनाकर दंड देने की घटना को लेकर व्यापक चर्चा और विवाद देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद इस मुद्दे ने राजनीतिक और सामाजिक बहस का रूप ले लिया। कुछ लोगों ने इसे बच्चों के सम्मान के खिलाफ अमानवीय व्यवहार बताया, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षकों को कुछ हद तक कठोर होने की आवश्यकता होती है। इस पूरे विवाद के बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन की भूमिका समाप्त हो रही है, या फिर हम अनुशासन और सम्मान के बीच संतुलन बनाने में असफल हो रहे हैं।

किसी भी घटना पर अंतिम राय बनाने से पहले उसका पूरा सच सामने आना आवश्यक होता है। कई बार अधूरी जानकारी या किसी एक वीडियो के आधार पर पूरे मामले का आकलन कर लिया जाता है, जबकि वास्तविकता उससे अलग भी हो सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसी घटनाओं की निष्पक्ष जांच हो और तथ्यों के आधार पर ही कोई निर्णय लिया जाए। बिना जांच के किसी शिक्षक को दोषी ठहराना उतना ही गलत है जितना कि बच्चों के साथ किसी प्रकार के अपमानजनक व्यवहार को उचित ठहराना। भारतीय समाज में विद्यालय केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं रहा है, बल्कि वह बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण की एक महत्वपूर्ण संस्था भी रहा है। विद्यालयों में शिक्षा के साथ-साथ अनुशासन, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों की भी शिक्षा दी जाती है। लंबे समय तक भारतीय शिक्षा प्रणाली में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षकों को कुछ हद तक कठोर होने की सामाजिक स्वीकृति भी रही है।

पुराने समय में छात्रों को कान पकड़ना, मुर्गा बनना या डांट पड़ना जैसी सजाएं असामान्य नहीं मानी जाती थीं। कई लोग आज भी अपने छात्र जीवन की ऐसी घटनाओं को याद करते हैं और मानते हैं कि उन अनुभवों ने उन्हें जिम्मेदार और अनुशासित नागरिक बनने में मदद की। यह भी सच है कि उस दौर में सरकारी विद्यालयों से पढ़े हुए अनेक छात्र आगे चलकर देश के बड़े अधिकारों, शिक्षक, वैज्ञानिक और प्रशासक बने। उस समय शिक्षा के साथ अनुशासन का गहरा संबंध माना जाता था। शिक्षक को केवल एक कर्मचारी नहीं, बल्कि शुरु के रूप में देखा जाता था और समाज में उनका विशेष सम्मान होता था। माता-पिता भी शिक्षकों के निर्णयों पर भरोसा करते थे और बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते थे।

लेकिन समय के साथ समाज में कई बदलाव आए हैं। बच्चों के अधिकारों, गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ी है। यह बदलाव सकारात्मक भी है, क्योंकि किसी भी बच्चे के साथ सकारात्मक या हिंसक व्यवहार स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाना और उनके व्यक्तित्व का विकास करना है। यदि किसी दंड के कारण बच्चे के आत्मसम्मान को दोषी ठहराना उतना ही गलत है जितना कि बच्चों के साथ किसी प्रकार के अपमानजनक व्यवहार को उचित ठहराना। भारतीय समाज में विद्यालय केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं रहा है, बल्कि वह बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण की एक महत्वपूर्ण संस्था भी रहा है। विद्यालयों में शिक्षा के साथ-साथ अनुशासन, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों की भी शिक्षा दी जाती है। लंबे समय तक भारतीय शिक्षा प्रणाली में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षकों को कुछ हद तक कठोर होने की सामाजिक स्वीकृति भी रही है।

सख्ती नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी छोटी घटना को लेकर विवाद खड़ा हो सकता है। कई बार शिक्षक इस भय में रहते हैं कि उनकी किसी कार्रवाई को गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ शिक्षक अनुशासन लागू करने से ही बचने लगते हैं। जब शिक्षक ही असमंजस और भय के माहौल में होंगे, तो शिक्षा व्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। दूसरी ओर यह भी सच है कि हर प्रकार की सजा को अनुशासन का नाम देकर सही नहीं ठहराया जा सकता। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को डराना नहीं, बल्कि प्रेरित करके आगे बढ़ाना होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा पद्धति इस बात पर जोर देती है कि अनुशासन का निर्माण सकारात्मक तरीकों से किया जाए। संवाद, मार्गदर्शन और प्रेरणा के माध्यम से भी बच्चों में अनुशासन विकसित किया जा सकता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब समाज इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच संतुलन नहीं बना पाता। एक ओर ऐसे लोग हैं जो किसी भी प्रकार की सख्ती को गलत मानते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि बिना कठोरता के अनुशासन संभव नहीं है। वास्तविक समाधान शायद इन दोनों के बीच कहीं मौजूद है। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शिक्षा से जुड़े मुद्दों को कई बार राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। किसी घटना को लेकर तुरंत आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं और मूल समस्या पर गंभीर चर्चा कम हो जाती है। शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय को राजनीतिक विवाद का माध्यम बनाना दीर्घकाल में शिक्षा व्यवस्था के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। समाज को यह समझना होगा कि शिक्षा केवल अधिकारों की चर्चा से आगे नहीं बढ़ सकती। अधिकारों के साथ जिम्मेदारियों का भी महत्व होता है। छात्रों को भी यह समझना चाहिए कि

विद्यालय में अनुशासन का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है। उसी तरह शिक्षकों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि अनुशासन के नाम पर कोई ऐसा व्यवहार न हो जिससे बच्चों की गरिमा को ठेस पहुंचे। माता-पिता की भूमिका भी इस पूरी प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले माता-पिता विद्यालय और शिक्षक के साथ मिलकर बच्चों के विद्यालय में सहयोग करते थे। आज कई बार विद्यालय, शिक्षक और माता-पिता के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती है। यह स्थिति बच्चों के हित में नहीं है। यदि तीनों पक्ष—विद्यालय, शिक्षक और अभिभावक—एक साथ मिलकर काम करें, तो बच्चों के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा सकता है। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं—शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार से जुड़ी अपेक्षाएं, तकनीकी बदलाव और सामाजिक बच्चों के विद्यालय में सहयोग करते थे। आज कई बार विद्यालय, शिक्षक और माता-पिता के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती है। यह स्थिति बच्चों के हित में नहीं है। यदि तीनों पक्ष—विद्यालय, शिक्षक और अभिभावक—एक साथ मिलकर काम करें, तो बच्चों के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा सकता है। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं—शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार से जुड़ी अपेक्षाएं, तकनीकी बदलाव और सामाजिक बच्चों के विद्यालय में सहयोग करते थे। आज कई बार विद्यालय, शिक्षक और माता-पिता के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती है। यह स्थिति बच्चों के हित में नहीं है। यदि तीनों पक्ष—विद्यालय, शिक्षक और अभिभावक—एक साथ मिलकर काम करें, तो बच्चों के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा सकता है। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं—शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार से जुड़ी अपेक्षाएं, तकनीकी बदलाव और सामाजिक बच्चों के विद्यालय में सहयोग करते थे। आज कई बार विद्यालय, शिक्षक और माता-पिता के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती है। यह स्थिति बच्चों के हित में नहीं है। यदि तीनों पक्ष—विद्यालय, शिक्षक और अभिभावक—एक साथ मिलकर काम करें, तो बच्चों के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा सकता है। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं—शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार से जुड़ी अपेक्षाएं, तकनीकी बदलाव और सामाजिक बच्चों के विद्यालय में सहयोग करते थे। आज कई बार विद्यालय, शिक्षक और माता-पिता के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती है। यह स्थिति बच्चों के हित में नहीं है। यदि तीनों पक्ष—विद्यालय, शिक्षक और अभिभावक—एक साथ मिलकर काम करें, तो बच्चों के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा सकता है। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं—शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार से जुड़ी अपेक्षाएं, तकनीकी बदलाव और सामाजिक बच्चों के विद्यालय में सहयोग करते थे। आज कई बार विद्यालय, शिक्षक और माता-पिता के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती है। यह स्थिति बच्चों के हित में नहीं है। यदि तीनों पक्ष—विद्यालय, शिक्षक और अभिभावक—एक साथ मिलकर काम करें, तो बच्चों के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा सकता है। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं—शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार से जुड़ी अपेक्षाएं, तकनीकी बदलाव और सामाजिक बच्चों के विद्यालय में सहयोग करते थे। आज कई बार विद्यालय, शिक्षक और माता-पिता के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती है। यह स्थिति बच्चों के हित में नहीं है। यदि तीनों पक्ष—विद्यालय, शिक्षक और अभिभावक—एक साथ मिलकर काम करें, तो बच्चों के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा सकता है। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं—शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार से जुड़ी अपेक्षाएं, तकनीकी बदलाव और सामाजिक बच्चों के विद्यालय में सहयोग करते थे। आज कई बार विद्यालय, शिक्षक और माता-पिता के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती है। यह स्थिति बच्चों के हित में नहीं है। यदि तीनों पक्ष—विद्यालय, शिक्षक और अभिभावक—एक साथ मिलकर काम करें, तो बच्चों के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा सकता है। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं—शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार से जुड़ी अपेक्षाएं, तकनीकी बदलाव और सामाजिक बच्चों के विद्यालय में सहयोग करते थे। आज कई बार विद्यालय, शिक्षक और माता-पिता के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती है। यह स्थिति बच्चों के हित में नहीं है। यदि तीनों पक्ष—विद्यालय, शिक्षक और अभिभावक—एक साथ मिलकर काम करें, तो बच्चों के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा सकता है। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं—शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार से जुड़ी अपेक्षाएं, तकनीकी बदलाव और सामाजिक बच्चों के विद्यालय में सहयोग करते थे। आज कई बार विद्यालय, शिक्षक और माता-पिता के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती है। यह स्थिति बच्चों के हित में नहीं है। यदि तीनों पक्ष—विद्यालय, शिक्षक और अभिभावक—एक साथ मिलकर काम करें, तो बच्चों के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा सकता है। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं—शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार से जुड़ी अपेक्षाएं, तकनीकी बदलाव और सामाजिक बच्चों के विद्यालय में सहयोग करते थे। आज कई बार विद्यालय, शिक्षक और माता-पिता के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती है। यह स्थिति बच्चों के हित में नहीं है। यदि तीनों पक्ष—विद्यालय, शिक्षक और अभिभावक—एक साथ मिलकर काम करें, तो बच्चों के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा सकता है। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं—शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार से जुड़ी अपेक्षाएं, तकनीकी बदलाव और सामाजिक बच्चों के विद्यालय में सहयोग करते थे। आज कई बार विद्यालय, शिक्षक और माता-पिता के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती है। यह स्थिति बच्चों के हित में नहीं है। यदि तीनों पक्ष—विद्यालय, शिक्षक और अभिभावक—एक साथ मिलकर काम करें, तो बच्चों के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा सकता है। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं—शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार से जुड़ी अपेक्षाएं, तकनीकी बदलाव और सामाजिक बच्चों के विद्यालय में सहयोग करते थे। आज कई बार विद्यालय, शिक्षक और माता-पिता के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती है। यह स्थिति बच्चों के हित में नहीं है। यदि तीनों पक्ष—विद्यालय, शिक्षक और अभिभावक—एक साथ मिलकर काम करें, तो बच्चों के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा सकता है। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं—शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार से जुड़ी अपेक्षाएं, तकनीकी बदलाव और सामाजिक बच्चों के विद्यालय में सहयोग करते थे। आज कई बार विद्यालय, शिक्षक और माता-पिता के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती है। यह स्थिति बच्चों के हित में नहीं है। यदि तीनों पक्ष—विद्यालय, शिक्षक और अभिभावक—एक साथ मिलकर काम करें, तो बच्चों के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा सकता है। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं—शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार से जुड़ी अपेक्षाएं, तकनीकी बदलाव और सामाजिक बच्चों के विद्यालय में सहयोग करते थे। आज कई बार विद्यालय, शिक्षक और माता-पिता के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती है। यह स्थिति बच्चों के हित में नहीं है। यदि तीनों पक्ष—विद्यालय, शिक्षक और अभिभावक—एक साथ मिलकर काम करें, तो बच्चों के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा सकता है। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं—शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार से जुड़ी अपेक्षाएं, तकनीकी बदलाव और सामाजिक बच्चों के विद्यालय में सहयोग करते थे। आज कई बार विद्यालय, शिक्षक और माता-पिता के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती है। यह स्थिति बच्चों के हित में नहीं है। यदि तीनों पक्ष—विद्यालय, शिक्षक और अभिभावक—एक साथ मिलकर काम करें, तो बच्चों के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा सकता है। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं—शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार से जुड़ी अपेक्षाएं, तकनीकी बदलाव और सामाजिक बच्चों के विद्यालय में सहयोग करते थे। आज कई बार विद्यालय, शिक्षक और माता-पिता के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती है। यह स्थिति बच्चों के हित में नहीं है। यदि तीनों पक्ष—विद्यालय, शिक्षक और अभिभावक—एक साथ मिलकर काम करें, तो बच्चों के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा सकता है। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं—शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार से जुड़ी अपेक्षाएं, तकनीकी बदलाव और सामाजिक बच्चों के विद्यालय में सहयोग करते थे। आज कई बार विद्यालय, शिक्षक और माता-पिता के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती है। यह स्थिति बच्चों के हित में नहीं है। यदि तीनों पक्ष—विद्यालय, शिक्षक और अभिभावक—एक साथ मिलकर काम करें, तो बच्चों के लिए बेहतर वातावरण तैय

संक्षिप्त समाचार

छुईखदान जनपद पंचायत का बजट विवाद राज्य स्तर तक पहुंचा, संचालनालय से मांगा मार्गदर्शन

खैरागढ़ (समय दर्शन)। जनपद पंचायत छुईखदान में लंबे समय से चल रहे बजट विवाद ने अब राज्य प्रशासन का ध्यान खींच लिया है। उपसंचालक पंचायत गीत कुमार सिंह ने पंचायत संचालनालय नवा रायपुर को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा है। उपसंचालक ने पत्र में पूछा है कि यदि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 का बजट समय पर अनुमोदित नहीं हुआ है, तो क्या अब पोस्ट-फैक्टो स्वीकृति विधिसम्मत होगी या नहीं। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट 3 मार्च 2026 को तथा 2025-26 का बजट 5 मार्च 2026 को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है, जबकि नियमों के अनुसार बजट जनवरी से फरवरी के बीच स्वीकृति के लिए भेजा जाना चाहिए। उपसंचालक ने स्पष्ट किया कि पिछले दो वित्तीय वर्षों का बजट समय पर अनुमोदित नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट तैयार करने के लिए किन आधार अभिलेखों को मान्य माना जाए। इसके लिए उन्होंने वास्तविक आय-व्यय विवरण, कोषागार अभिलेख, लेखा पुस्तिकाएं और अन्य प्रमाणिक दस्तावेजों के उपयोग पर दिशा-निर्देश मांगे हैं। इधर, जनपद पंचायत के सभापति सुधीर गोलछा ने आरोप लगाया कि जनपद सीईओ और अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा बजट अनुमोदन और स्थायी समिति की स्वीकृति के बिना फर्जी बिलों के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने उपसंचालक से आग्रह किया है कि जब तक रायपुर से स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं आता सभी भुगतानों पर तत्काल रोक लगाई जाए। पिछले कई महीनों से जारी इस विवाद में सभापति सुधीर गोलछा, डोमर सिंह, ज्योति जधेल, राजिम मुखेश चंदेल समेत दर्जनभर से अधिक निवाचित जनप्रतिनिधियों ने लगातार शिकायतें की हैं। अब सबकी निगाहें राज्य संचालनालय की दिशा-निर्देश जारी करने और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं।

सोहागपुर में गौधाम का हुआ उद्घाटन



कोरवा (समय दर्शन) सोहागपुर में गौधाम सोहागपुर के उद्घाटन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक फूल सिंह राठिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में गौ सेवा आयोग जिला स्तरीय समिति कोरवा के अध्यक्ष विनय सिंह, जनपद सदस्य सुहागपुर श्रीमती अनसुईया राठौर, सांसद प्रतिनिधि श्री सहसराम कौशिक, उपसरपंच सुहागपुर विजय कुमार जांगड़े तथा गौ सेवा आयोग विकासखंड स्तरीय समिति करतला के अध्यक्ष श्री मारुति पटेल शामिल हुए। इसके अतिरिक्त कमल वैष्णव, शिव कुमार, उत्तम यादव, आयुष सकसेना तथा जगदीश कंवर (सदस्य, गौ सेवा आयोग विकासखंड स्तरीय समिति करतला) की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह हर्ष एवं उल्लास के वातावरण में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन गौधाम सोहागपुर समिति स्वर्गीय वैद्य नन्धुराम कौशिक चिचोली गौशाला, विकासखंड करतला द्वारा किया गया। इस आयोजन में गौशाला के अध्यक्ष श्री साखीराम कौशिक जी का विशेष एवं महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम के सफल आयोजन में पशुधन विकास विभाग करतला के समस्त स्टाफ का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। विभाग के डॉक्टर वीरेंद्र पाल कंवर सहित एमएफओ श्यामलाल बिड़वार, रमेश कंवर, राम सिंह कंवर, श्रीमती ललिता कंवर, वैभव जायसवाल, रघुवीर सिद्धार्थ तथा छबिलाल साहू ने कार्यक्रम के संचालन एवं व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समारोह के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अतिथियों ने गौरवपूर्ण और गौसेवा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गौधाम सोहागपुर के संचालन के लिए समिति के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों एवं गौसेवा से जुड़े लोगों की उपस्थिति रही, जिससे कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

नाव से शराब तस्करी कर रहे 01 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

आरोपी से 135 लीटर कच्ची महुआ शराब और तस्करी में प्रयुक्त नाव को किया गया जप्त

गिरफ्तार आरोपी : वीरेंद्र माझी पिता कीर्तन माझी उम्र 32 वर्ष सा महलपाली थाना रेंगाली जिला झारसुगडा उड़ीसा

सारंगढ बिलाईगढ़- (समय दर्शन) सारंगढ बिलाईगढ़ के पुलिस अधीक्षक अंजनेय वाण्य के द्वारा जिले के सभी थाना/चौकी प्रभारियों को अवैध शराब खरीदी विक्री,परिवहन में संलिप्त व्यक्तियों पर कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर अति0 पुलिस अधीक्षक श्रीमती



विभिधा पाण्डेय , उप पुलिस अधीक्षक सुश्री संतोषी ग्रेस के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी प्रमोद यादव के कुशल नेतृत्व मे उड़ीसा से नाव में शराब तस्करी कर रहे एक आरोपी को सरिया पुलिस को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।

विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 16/03/2026 को दौरान पेट्रोलिंग सूचना मिला कि महानदी में नाव में एक व्यक्ति भारी मात्रा में महुलपाली घाट उड़ीसा से शराब लेकर ग्राम तोरा की ओर रहा है कि सूचना मिलने पर मुखबिर के बताए स्थान महानदी घाट किनारे ग्राम तोरा में एक व्यक्ति नाव में आते मिला जिसे घेराबंदी कर पकड़कर नाम पता पूछने पर अपना नाम वीरेंद्र माझी पिता कीर्तन माझी उम्र 32 वर्ष सा महलपाली थाना रेंगाली जिला

झारसुगडा उड़ीसा का होना बताया जिसके कब्जे में नाव में रखे पांच बोरी में 750 पाउंड प्रत्येक पाउंड में 180 द्रव्य भरा हुआ *कुल 135 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब कीमती 27000* रु मिला।गवाहों के समक्ष महुआ शराब तथा घटना में प्रयुक्त **नाव कीमती 20000 रु कुल कीमती 47000 रु* को जप्त कर आरोपी के खिलाफथाना सरिया में अप क्र 52/2026 धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी प्रमोद यादव , प्र0आर0- मोहन गुप्ता,भोजराम नट आरक्षक- दिलीप खेही, दिगंबर पटेल,ताराचंद लक्ष्मी पटेल,सुरज शिदार और समस्त स्टाफका विशेष योगदान रहा।

पीडित आदिवासी महिला को मां बहन की अश्लील गाली गलौच, मारपीट कर सामूहिक बलात्कार के आरोपियों को थाना बालोद पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार



प्रकरण में जोड़ी गई है अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा

आरोपीगणों को गिरफ्तार कर भेजा गया जूडिशियल रिमांड पर

बालोद। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता आदिवासी महिला थाना बालोद जिला बालोद छग. ने लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि यह एक आदिवासी महिला जानते हुए गांव के विकास सिन्हा पिता रामस्वरूप सिन्हा, रोशन कुमार साहू पिता गिरधर साहू एवं कमल कुमार सेन पिता मनोहर लाल सेन सभी साकिनान करहीभदर के द्वारा दिनांक 22.02.2026 के रात्रि 09.00 बजे उत्तराकर ले गये और रात्रि 12.00 बजे तक मेरे साथ जबरदस्ती सामूहिक बलात्कार कर मां बहन की अश्लील गाली गलौच कर किसी को बतायेगी तो कोई यकीन नहीं करेगा कहकर सभी लोग पेट एवं बाया घुटने एवं शरीर के अन्य भाग में मारपीट किया है। मारपीट करने से मेरे पेट एवं बाया घुटने एवं शरीर के अन्य भाग में चोट आया है कि रिपोर्ट पर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 107/2026 धारा 296,115(2), 87, 70 (1) बी एन एस एवं 3(2)(बी) एएसटीएससी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

अपराध की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री योगेश

पटेल के मार्ग दर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोनिका ठाकुर के निर्देश एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बालोद बोनीफंस एका के पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में सायबर सेल बालोद टीम की सहयता से आरोपीगण विकास सिन्हा पिता रामस्वरूप सिन्हा उम्र 26 वर्ष 02. कमल कुमार सेन पिता मनोहर लाल सेन उम्र 23 वर्ष साकिनान करहीभदर थाना व जिला बालोद छग. को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जिन्होंने अपराध घटना करना स्वीकार किया व घटना के संबंध में ग्राम विकास समिति के समक्ष गुनाह स्वीकार कर अर्थ दण्ड देना बताया। आरोपियों के विरुद्ध धारा सदर का अपराध चटित करना पाये जाने से विधिवत् दिनांक 14.03.2026 के गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

आरोपीगणों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा, म.प्र.आर. नर्मदा कोठारी, प्र.आर. योगेश सिन्हा, प्र.आर. दुर्गेश यादव, आरक्षक मोहन कोकिला, संजय सोनी, बनवाली साहू, नागेश्वर साहू सायबर सेल प्रभारी धरम धुआर्य एवं सायबर टीम की विशेष योगदान रहा।

गिरफ्तार आरोपीगणों का नाम:-

01. विकास सिन्हा पिता रामस्वरूप सिन्हा उम्र 26 वर्ष पता- ग्राम करहीभदर थाना व जिला बालोद
02. कमल कुमार सेन पिता मनोहर लाल सेन उम्र 23 वर्ष पता-ग्राम करहीभदर थाना व जिला बालोद

कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समय सीमा की बैठक, लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए निर्देश

मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रगति की समीक्षा की, जिला अस्पताल व लाइवलीहुड कॉलेज में होगा संचालन

पीएम आवास योजना में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए - कलेक्टर

राजस्व पखवाड़ा व जनसमस्या निवारण शिविर में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के साथ शत प्रतिशत करें निराकरण

निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता के साथ करें पूर्ण, नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश

जल संचय एवं जनभागीदारी कार्यों को प्राथमिकता के साथ करें

जांजगीर-चांपा //समय दर्शन! कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने आज कलेक्टर

सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक लेकर विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय सीमा के लंबित प्रकरणों एवं प्राप्त शिकायतों का शीघ्र और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को समय पर राहत मिल सके। कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों के त्वरित समाधान तथा आमजन से जुड़े विकास कार्यों में तेजी लाने कहा।

कलेक्टर श्री महोबे ने जिले में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के निर्माण एवं उससे जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की निर्माण कार्य की सभी प्रक्रियाएं तय समय-सीमा में पूरी सुनिश्चित किया जाए। मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए वर्तमान में जिला अस्पताल और लाइवलीहुड कॉलेज भवन का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए दोनों भवनों में आवश्यक रिनोवेशन एवं मरम्मत कार्य कराने



के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जा सकें। कलेक्टर ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।

जिले में राष्ट्रीय टीकाकरण के अवसर पर सर्वाइकल कैसर से बचाव के उद्देश्य से एचपीव्ही वैक्सीन अभियान का हुआ शुभारंभ

एचपीव्ही टीकाकरण अभियान के तहत कलेक्टर ने टीका लगवाने वाली बालिकाओं को दिया प्रमाण पत्र

जांजगीर-चांपा //समय दर्शन /// राष्ट्रीय टीकाकरण के अवसर पर गर्भाशय के मुख के कैसर (सर्वाइकल कैसर) से बचाव के उद्देश्य से जिले में मानव पैपिलोमा वायरस (एचपीव्ही) से बचाव के लिए विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे की उपस्थिति में आज जिला चिकित्सालय जांजगीर-चांपा में एचपीव्ही टीकाकरण किया गया। इस दौरान बालिकाओं को एचपीव्ही वैक्सीन लगाई गई तथा उन्हें



टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी दी गई एवं कलेक्टर ने प्रमाण पत्र का वितरण किया। कलेक्टर ने कहा कि यह टीकाकरण अभियान यह टीकाकरण महिलाओं में होने वाले गर्भाशय के मुख के उपस्थिति में आज जिला कैसर (सर्वाइकल कैसर) से बचाव के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इस

अभियान के अंतर्गत जिले के लगभग 16,000 बालिकाओं को एचपीव्ही वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रविवार एवं शासकीय अवकाश को छोड़कर नियमित रूप से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एचपीव्ही वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, शासकीय अस्पतालों में यह टीका बालिकाओं

को केवल एक बार लगाया जाएगा, जो पूर्णतः निःशुल्क है। टीकाकरण के लिए बालिकाओं को अपने अभिभावक के साथ जिला चिकित्सालय आना आवश्यक है। साथ ही आयु सत्यापन के लिए आधार कार्ड अथवा जन्म प्रमाण पत्र तथा पंजीयन हेतु अभिभावक का मोबाइल नंबर लाना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर श्री महोबे ने जिले के सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी 14 वर्ष की बालिकाओं को एचपीव्ही वैक्सीन लगावाकर उन्हें सर्वाइकल कैसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित बनाने में सहयोग करें। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉ अनिता श्रीवास्तव, सिविल सर्जन डॉ एस कुजुर सहित चिकित्सकगण व संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

केक एंड क्रीम स्वीट सेंटर में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

सारंगढ-बिलाईगढ़, टारजन महेश(समय दर्शन) जिले के बरमकेला ब्लॉक मुख्यालय में रविवार देर रात एक भीषण आगजनी की घटना ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। यहाँ स्थित प्रसिद्ध 'केक एंड क्रीम स्वीट सेंटर' में अचानक लगी आग से दुकान के भीतर रखी कीमती मशीनें, कच्चा माल और अन्य फर्नीचर जलकर पूरी तरह खाक हो गए। इस घटना में संचालक को लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है।

देर रात धधक उठी लपटें-मिली जानकारी के अनुसार, घटना रविवार रात की है जब दुकान बंद हो चुकी थी। देर रात अचानक दुकान के भीतर से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों ने शोर मचाया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब



तक दुकान के अंदर रखे फ्रिज, ओवन, डिस्टले कार्टर और मिठाई बनाने की मशीनें आग की चपेट में आ चुकी थीं।

एक घण्टे में तीसरी घटना, बड़ी चिंता- बरमकेला और आसपास के इलाकों में आगजनी की यह कोई पहली घटना नहीं है। गौरतलब है कि पिछले एक सप्ताह के भीतर क्षेत्र में आगजनी की यह तीसरी बड़ी घटना है। लगातार हो रही इन घटनाओं ने व्यापारियों और आम जनता के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन और फायर विभाग की ओर से बरती जा रही सावधानी और संसाधनों की उपलब्धता पर भी अब सवाल उठने लगे हैं।

साधधानी की अपील: क्षेत्र में बढ़ती आगजनी की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने सभी दुकानदारों और संस्थानों से अपने बिजली कनेक्शन की जांच कराने और अग्निशमन यंत्र दुरुस्त रखने की अपील की है।

दिए। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि पुलिस, परिवहन और स्वास्थ्य विभाग आपसी समन्वय के साथ सभी दुर्घटनाओं की जानकारी पोर्टल में अनिवार्य रूप से दर्ज करें। कलेक्टर ने जिले में चल रहे निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। कलेक्टर ने कहा कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार समय-सीमा में पूर्ण करें।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि घरेलू गैस सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने, घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंधित करने और संबंधित विभाग को नियमित जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें। कलेक्टर ने स्कूल शिक्षा विभाग को विद्यार्थियों का आधार अपडेट करने और आईडी बनाने के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग एवं ऑफिस

के माध्यम से निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों का आधार पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने जल संचय एवं जनभागीदारी से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण से संबंधित गतिविधियों में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व पखवाड़ा एवं जनसमस्या निवारण शिविरों में प्राप्त सभी आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री गोकुल रावटे, अपर कलेक्टर श्री ज्ञानेश्वर सिंह ठाकुर, अपर कलेक्टर आर. आर. के तन्वोली, संयुक्त कलेक्टर श्री संदीप सिंह ठाकुर सहित जिला स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

खबर-खास

ई-ऑफिस क्रियान्वयन में दुर्ग जिला प्रदेश में द्वितीय स्थान पर, -कलेक्टर सिंह के मार्गदर्शन में मिली बड़ी सफलता

दुर्ग/ सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, गतिशीलता और पेपरलेस गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई ई-ऑफिस प्रणाली के संचालन में दुर्ग जिले ने पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, ई-फाइल काउंट के मामले में दुर्ग जिला 9,957 फाइलों के साथ पूरे प्रदेश में द्वितीय स्थान पर काबिज हो गया है। यह उपलब्धि कलेक्टर श्री अभिजित सिंह के कुशल मार्गदर्शन और उनके द्वारा की गई निरंतर मॉनिटरिंग का प्रतिफल है। जिले में इस प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को उच्च स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिससे कार्यालयीन फाइलों के निपटान में तेजी आई है जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनी है। कलेक्टर श्री सिंह ने स्पष्ट किया है कि ई-ऑफिस केवल एक सॉफ्टवेयर मात्र नहीं, कार्य संस्कृति में एक क्रांतिकारी बदलाव है, जिससे आम जनता के कार्यों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित हो रहा है। प्रदेश स्तर पर ई-ऑफिस की वर्तमान स्थिति के अनुसार सक्ती जिला प्रथम स्थान पर बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि सक्ती जिले को शासन द्वारा ई-ऑफिस के सफल क्रियान्वयन के लिए एक 'प्रयोग जिले' के रूप में विकसित किया गया था, जहाँ शुरुआती दौर में इस तकनीक का व्यापक परीक्षण किया गया। इस मॉडल डिस्ट्रिक्ट पहल के कारण सक्ती जिले को आंकड़ों में उल्लेखनीय बढ़त प्राप्त हुई है। हालांकि, दुर्ग जिले ने अपनी सक्रियता और बेहतर प्रशिक्षण रणनीति के माध्यम से बहुत कम समय में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के अनुरूप, जिले के सभी सरकारी विभागों में अब भौतिक फाइलों के स्थान पर डिजिटल फाइलों के चलन को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे भविष्य में 'जीरो पेपर्स' के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी मदद मिलेगी।

उप निरीक्षक सुकांत पाण्डेय : आबकारी अधिकारी या वसूली का मास्टरमाइंड...? आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन के जिला में अवैध वसूली का खेल

कोरबा/पाली : (समय दर्शन) कोरबा जिला के पाली ब्लॉक में तैनात आबकारी अधिकारी उप निरीक्षक सुकांत पाण्डेय पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लग रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, सुकांत पाण्डेय देशी और अंग्रेजी शराब के साथ-साथ महुआ दारू और गंजा का कारोबार करने वालों से जगह-जगह वसूली कर रहे हैं। वे शराब के ठेकेदारों और विक्रेताओं से मोटी रकम लेकर उन्हें अवैध रूप से शराब बेचने की

अनुमति दे रहे हैं। इस अवैध वसूली के लिए सुकांत पाण्डेय ने अपने कुछ खास लोगों का नेटवर्क बना रखा है जो पाली ब्लॉक अंतर्गत पूरे ग्रामीण एरिया में भ्रमण कर अवैध शराब माफिया का हौसला बढ़ा रहा है जो शराब के ठेकेदारों और विक्रेताओं से संपर्क में रहते हैं और उनसे वसूली की रकम तय करते हैं। इसके बाद उप निरीक्षक सुकांत पाण्डेय खुद या अपने आदमियों के माध्यम से वसूली की रकम लेते हैं,



फैम पे पर या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म जैसे-किराना दुकान, या किसी अन्य व्यक्ति के फर्म पे में वसूली करते हैं। पाली में अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने होंगे। उप निरीक्षक सुकांत पाण्डेय के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है, लोगों का कहना है कि उप निरीक्षक सुकांत पाण्डेय के कारण पाली ब्लॉक में शराब का अवैध और गंजा

कारोबार बढ़ गया है और इससे समाज में नशे की लार बढ़ रही है। अवैध वसूली की मांग- उप निरीक्षक सुकांत पाण्डेय के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है। लोगों का कहना है कि सुकांत पाण्डेय को तुरंत निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ जांच शुरू की जाए। इसके अलावा, पाली में अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने होंगे।

सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा कैंसर) से बचाव हेतु टीकाकरण अभियान की शुरुआत



जिले में आज 5 किशोरियों ने लगाई एचपीवी की वैक्सीन

गरियाबंद (समय दर्शन) कलेक्टर बीएस उडके के निर्देश पर तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ यूएस नवरब के मार्गदर्शन में भारत सरकार के नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए आज जिला अस्पताल गरियाबंद में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। जिसमें 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर

चुकी किशोरियों को एचपीवी वैक्सीन लगाकर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। आज कुल 5 किशोरियों फजल चौधरी, अंजू सोम, कल्पना यादव, लबली ठाकुर और मिनाक्षी मानिकपुरी को एचपीवी वैक्सीन लगाई गई। टीका लगाए जाने के बाद इन सभी लाभार्थियों को 30 मिनट तक निगरानी कक्ष में रखा गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में 6 हजार किशोरियों को टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह

वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में अत्यंत प्रभावी है और किशोरियों के स्वास्थ्य संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पात्रता के अनुसार वे किशोरियाँ टीकाकरण के लिए चयनित होंगी। जिन्होंने अपना 14वां जन्मदिन मना लिया है लेकिन 15वां जन्मदिन नहीं मनाया है इसके लिए आधार कार्ड, अन्य पहचान पत्र या अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मान्य होगा। जिला अस्पताल में यह टीकाकरण नियमित रूप से जारी रहेगा। कार्यक्रम में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. हरीश चौहान, जिला टीकाकरण अधिकारी, जिला मलेरिया, अस्पा, अस्पा ल प्रबंधक, विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक, सेक्टर सुपरवाइजर, स्टाफ नर्स, मितानिन और हितग्राहियों के परिजनों उपस्थित थे।

एक दिवसीय शिव कथा सत्संग मेला का भव्य आयोजन, श्रद्धालुओं ने सुनी भगवान शिव की महिमा



भक्ति, भजन और कथा से गुंजा पूरा परिसर, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल

गरियाबंद (समय दर्शन)। नगर के बजरंग चौक के पीपलेश्वर महादेव में एक दिवसीय शिव कथा सत्संग मेला का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान शिव की महिमा का श्रवण किया। कार्यक्रम की शुरुआत में भगवान शिव पार्वती और हनुमान भगवान की विधि-विधान से पूजा-अर्चना और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कथा वाचक ने भगवान शिव के जीवन, उनके त्याग, तपस्या और मानव कल्याण के संदेशों का विस्तृत वर्णन करते हुए श्रद्धालुओं को धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी।

कार्यक्रम के दौरान कथा वाचक ने भगवान शिव के जीव न, उन के त्याग, करुणा और मानव कल्याण के संदेशों को विस्तार से बताया। कथा के दौरान कथा वाचन धमतीरी जिले के सोरिंद निवासी मनोज दुबे महाराज ने बताया गया कि भगवान शिव केवल संहार के देव नहीं बल्कि सृष्टि के रक्षक और कल्याणकारी देवता हैं। उन्होंने प्रेरणा दी। शिव कथा सुनने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा परिसर हर-हर महादेव के जयकारों से गुंजा उठा। कार्यक्रम में भजन-कीर्तन और सत्संग का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालु भक्तिभाव में झूम उठे। आयोजन समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था की गई थी। आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में आध्यात्मिकता, भाईचारे और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम के सफल आयोजन में समिति के सदस्यों और वार्ड के नागरिकों का विशेष सहयोग रहा।

पुलिस कप्तान की पहल जिले के अधिकारी/कर्मचारियों के लिए कार्यालय में साप्ताहिक प्रशिक्षण, कार्यशाला का आयोजन

गरियाबंद (समय दर्शन)। पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर के निर्देशन में 16 मार्च से 21 मार्च 2026 तक जिला पुलिस कार्यालय में जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल की कार्यक्षमता को बढ़ाना और उन्हें प्रशासनिक व तकनीकी प्रक्रियाओं में दक्ष बनाना है।

कार्यशाला के दौरान कर्मचारियों को उनकी सेवा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे सर्विस रिकार्ड के संधारण, वेतन

निर्धारण, यात्रा भत्ता (टीए) और पेंशन संबंधी नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। इसका उद्देश्य विभाग में पारदर्शिता लाना और कर्मचारियों के व्यक्तिगत सेवा मामलों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करना है। विवेचकों को बदलते अपराधों के दौर में पुलिस को आधुनिक बनाने हेतु साइबर अपराधों की रोकथाम और जांच के व्यावहारिक गुण सिखाए गए। साथ ही छष्ट्रहृद (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स) पर डेटा एंटी और ऑनलाइन रिकार्ड संधारण को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। भारत सरकार के द्वचक्र 'मिशन

मोदी टेक्नोलॉजी नहीं आया काम, नाले की गैस से नहीं बना चाय

महंगाई पर भाजपा सरकार को घेरा

गरियाबंद (समय दर्शन)। गरियाबंद जिले की तहसील मुख्यालय मैनपुर नगर में आज सोमवार को ब्लॉक कांग्रेस कमिटी मैनपुर द्वारा रसोई गैस की कमियों में बढ़ोतरी एवं गैस की किल्लत को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले कांग्रेसियों ने गैस सिलेंडर का यात्रा निकाली रैली में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया गया यहाँ रैली नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए बस स्टैंड पहुंची और वापस पंचायत कार्यालय के सामने नाली में चाय बनाने का प्रदर्शन किया इस अनोखे प्रदर्शन को देखने भारी भीड़ लगी रही और लोगों ने जमकर आनंद लिया कांग्रेस के इस अनोखे प्रदर्शन का पूरे नगर व क्षेत्र में जमकर चर्चा हो रही है और लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं तो सोशल मीडिया में भी जमकर नाली में चाय बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है, मैनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क किनारे नाले की गैस से चाय बनाने की कोशिश कर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध जताया, हालांकि यह प्रयास सफल नहीं हो सका, लेकिन इस प्रतीकात्मक प्रदर्शन ने राहगीरों और स्थानीय लोगों का ध्यान खींच लिया। दरअसल, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा नाले की गैस से



चाय बनाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने शहर में यह प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। यह प्रदर्शन ब्लॉक कांग्रेस कमिटी मैनपुर अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव के नेतृत्व में किया गया, कांग्रेस कार्यकर्ता चाय बनाने के बर्तन और कुल्हड़ लेकर नाले के पास पहुंचे और चूल्हा जलाकर चाय बनाने का प्रयास किया इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नाले की गैस से चाय बनाने जैसी बातें करते हैं, लेकिन इससे आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता। उन्होंने कहा कि आज घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत बढ़

रही है और लोग इससे परेशान हैं, जबकि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव ने आरोप लगाया कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और गैस सिलेंडर आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। उनका कहना था कि इन समस्याओं के बावजूद भाजपा सरकार जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन सरकार को आम जनता की परेशानियों की याद दिलाने के लिए किया गया है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से चाय बनाकर लोगों को पिलाने की भी कोशिश की सड़क किनारे हुए इस अनोखे प्रदर्शन को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ भी जुट गई और यह पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना रहा। इस दौरान प्रमुख रूप से जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष संजय नेताम, ब्लाक कांग्रेस मैनपुर अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव, महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका कपिल, युवा कांग्रेस अध्यक्ष सोहन नागेश, महामंत्री गेन्दू यादव, शाहिद मेमन, सावंत शर्मा, जाकीर रजा, पूरन मेश्राम, नजीब बेग, पदूलोचन यादव, इमरान खान, दुलेन्द्र नेगी, मुकेश कपिल, दयाराम यादव, रोशन राठौर, डोमार साहू, गुंजेश कपिल, उपासिन नागेश, दादू, राकेश ध्रुव, तरुण कपिल, हबीब मेमन, सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे।

| कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग | | | | | |
|--|--------------|--|--|---|---|
| नामांतरण सूचना विज्ञप्ति क्रमांक 54 वर्ष 2025-26 | | | | | |
| सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 धारा 167 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों के उनके नाम के सामने भूमि/भवन स्वामित्व परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। संबंधित हित वाले व्यक्ति सूचना प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर अपने आपत्ति लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। समयावधि के पश्चात आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। | | | | | |
| क्रं. | ना.प्र. क्र. | क्रेता का नाम | विक्रेता का नाम | वार्ड क्रमांक | नाम परिवर्तन का आधार जिस पर दावा/आपत्ति की जाती है |
| 1177 | 1177 | अभिलाषा, मुनेश्वर/ अजय मुनेश्वर | नलिनी देशपांडे / डी.के.देशपांडे, संयोग कुमार/चंद्रशेखर, आशा डी. के. देशपांडे | वार्ड क्र.11 शंकर नगर (पूर्व) दुर्ग | पंजीकृत बयानमा |
| 1178 | 1178 | किरण जीत कौर/ बलवीर सिंह | श्याम कंस्ट्रक्शन पार्टनर प्रतीक अग्रवाल/ सुरेश कुमार अग्रवाल | वार्ड क्र.23, दीपक नगर दुर्ग | पंजीकृत बयानमा |
| 1179 | 1179 | दीपक कुमार जैन/राजा राम जैन | श्याम कंस्ट्रक्शन पार्टनर प्रतीक अग्रवाल/सुरेश कुमार अग्रवाल | वार्ड क्र.23, दीपक नगर दुर्ग | पंजीकृत बयानमा |
| 1180 | 1180 | लक्ष्मीकान्त साहू/रूपाराम साहू | राधेन्द्र कुमार शर्मा/बी.पी.शर्मा | वार्ड क्र. 51, बोरसी (उत्तर) दुर्ग | पंजीकृत बयानमा |
| 1181 | 1181 | शीला विश्वकर्मा/रामफेर विश्वकर्मा | तुलसीराम साहू, जहोर अहमद/ बशीर अहमद | वार्ड क्र. 42, कसारीडीह (पश्चिम) दुर्ग | पंजीकृत बयानमा |
| 1182 | 1182 | सुनीता सुराना/आलोक सुराना | इंदरचंद्र सुराना/स्व. सुगनचंद्र जी सुराना | वार्ड क्र.36, गंजपारा वार्ड, दुर्ग | दानपत्र |
| 1183 | 1183 | अनिल अग्रवाल/ स्व. अरविन्द अग्रवाल | भगवती बाई/अम्बिका प्रसाद अग्रवाल | वार्ड क्र.27, पोलसाय पारा, दुर्ग | मृत्यु प्रमाण पत्र, ऋण प्रतिलिपि |
| 1184 | 1184 | यशोदा राव/ व्ही.श्रीनिवास राव | मासुम बाफना/ मितेश बाफना | वार्ड क्र.53, पोर्टियाकला, (उत्तर) दुर्ग | पंजीकृत बयानमा |
| 1185 | 1185 | नेहा जैन/अमित जैन | सुरजीत बाई/रावलमलजी एवं सरोज गोलछा/सतीशचंद्र गोलछा, संदीप जैन/स्व.रावलमल जैन | वार्ड क्र.39 कचहरी बाई, दुर्ग | पंजीकृत बयानमा |
| 1186 | 1186 | गुरुमति साहू/लोकेन्द्र साहू, आकांक्षा साहू, लोकेन्द्र साहू, ज्ञानेश कुमार साहू/ लोकेन्द्र साहू | लोकेन्द्र साहू / देववार साहू | वार्ड क्र.40, कसारीडीह, दुर्ग | नगर तथा नगरपालिका क्षेत्रों के ग्रामों के लिए नामा.पी. एवं मृत्यु प्रमाण पत्र |
| 1187 | 1187 | लोकेश्वरी डारहे/ओमप्रकाश डारहे | दशरू राम कुरै/स्व.मनी राम कुरै | वार्ड क्र.50, बोरसी (पूर्व), दुर्ग | सम्पदा अधिकारी छ.ग.गृह निर्माण का आदेश पारित दिनांक 10.03.2023 |
| 1188 | 1188 | लक्ष्मी नारायण साहू/ स्व.चंद्रलाल साहू | चंद्रलाल साहू/ नेहर सिंह साहू/ मिश्री लाल साहू/ स्व. चंद्रलाल साहू, चंद्रिका साहू, / स्व. चंद्रलाल साहू, कुसुम बाई/ स्व. चंद्रलाल साहू, ताकेश्वरी साहू/स्व. चंद्रलाल साहू, रमौतिन बाई साहू, / स्व. चंद्रलाल साहू | वार्ड क्र.38, मिलपारा दुर्ग | हकत्याग पत्र |
| 1189 | 1189 | रोली चन्द्राकर/डॉ. कुणाल चन्द्राकर | बाबूलाल कौशिक/बुधराम | वार्ड क्र.49, बोरसी (पश्चिम) दुर्ग | सेलडीड |
| 1190 | 1190 | रोली चन्द्राकर/डॉ. कुणाल चन्द्राकर | योगेन्द्र कौशिक/ बाबूलाल चन्द्राकर | वार्ड क्र.49, बोरसी (पश्चिम) दुर्ग | सेलडीड |
| 1191 | 1191 | प्रियंका वर्मा /मनेन्द्र कुमार वर्मा | रवि शर्मा/स्व. शंकर लाल जी शर्मा | वार्ड क्र.49, बोरसी (दक्षिण) दुर्ग | पंजीकृत बयानमा |
| 1192 | 1192 | चंचल ताम्रकार/विक्रान्त ताम्रकार | शिव ताम्रकार, पवन कुमार ताम्रकार, रामवरुण ताम्रकार, कुमारी सुशीला ताम्रकार/ स्व. प्रेमलाल ताम्रकार | वार्ड क्र.32, ब्राह्मणपारा दुर्ग | पंजीकृत बयानमा |
| 1193 | 1193 | शुभम तिवारी/शशांक तिवारी | शुभा तिवारी/मां कर्मा डेहलपर्स प्रकाश शर्मा/धिरंजीलाल शर्मा | वार्ड क्र.54, पोर्टियाकला, (दक्षिण) दुर्ग | पंजीकृत बयानमा |
| 1194 | 1194 | रामू पटेल/फागूराम पटेल | नेतराम निषाद/भुरूराम निषाद | वार्ड क्र.03, मठपारा (दक्षिण) दुर्ग | पंजीकृत बयानमा |
| 1195 | 1195 | किरण कुमार यदु/काशी राम यदु | ललिता यादव/स्व. दुर्गा शंकर यादव | वार्ड क्र.18 औद्योगिक नगर (दक्षिण) दुर्ग | दानपत्र |
| 1196 | 1196 | सारिका देवी /बलराम | विक्रलेश कुमार यादव/कमल यादव | वार्ड क्र.52, बोरसी (दक्षिण) दुर्ग | पंजीकृत बयानमा |

राजस्व अधिकारी नगर पालिक निगम, दुर्ग

